

351.05
H57R277.02
HP-8051
1-25

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड : 50	शिमला, शनिवार, 3 अगस्त, 2002/12 श्रावण, 1924	संख्या : 18
विषय सूची		
भाग-1	वैधानिक नियमों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	776
भाग-2	वैधानिक नियमों को छोड़कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	—
भाग-3	अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाईनैन्शियल कमिशनर तथा कमिशनर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि	777—785
भाग-4	स्थानीय स्वायत्त शासन, म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाऊन एरिया तथा पंचायती राज विभाग	—
भाग-5	वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन	786—791
भाग-6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन	792—804
भाग-7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं	—
—	अनुपूरक	—

3 अगस्त, 2002/12 श्रावण, 1924 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित विज्ञापितों 'असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश' में प्रकाशित हुईं: —

विज्ञापित की संख्या	विभाग का नाम	विषय
संख्या गृह-सी० (ई) 5-8/2001, दिनांक 11 जुलाई, 2002.	गृह विभाग	आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 23 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत "विशेष न्यायालयों" के गठन बारे अधिसूचना का प्रकाशन (इसके अंग्रेजी रूपान्तर सहित)।
संख्या टी० पी० जे० एफ० (6)-2/2002, दिनांक 26 जुलाई, 2002.	परिवहन विभाग	हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकलज टैक्सेशन (प्रथम संशोधन) रुल्ज, 2002 का प्रकाशन (इसके अंग्रेजी रूपान्तर सहित)।
संख्या 3-7/2001-ई० एल० एन०, दिनांक 27 जुलाई, 2002.	निर्वाचन विभाग	भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56/2002/न्यायिक-III, दिनांक 12 जुलाई, 2002 का प्रकाशन।

भाग-1— वैधानिक नियमों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट

NOTIFICATIONS

Shimla-1, the 20th July, 2002

No. HHC/GAZ/14-58/75-X-14908.—The result of 40th Departmental Examination of the Subordinate Judges (Members of the Himachal Pradesh Judicial Services) held in June, 2002, is hereby published for information of all concerned as required under sub-rule (ix) of Rule 4 part III-C of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 1973 read with Rule 17(x) of the Himachal Pradesh Judicial Service (Departmental Examination) Rules, 1976.

(By order,

SURJIT SINGH,
Registrar General.

ANNEXURE-A.

RESULT OF 40TH DEPARTMENTAL EXAMINATION HELD IN THE MONTH OF JUNE, 2002 FOR THE MEMBERS OF HIMACHAL PRADESH JUDICIAL SERVICE

Note.—WITH CREDIT (WC) means passed by obtaining 3/4th of maximum marks, "HIGHER STANDARD (HS)" means passed by obtaining 2/3rd of the maximum marks, "LOW STANDARD (LS)" means passed in the lower standard by obtaining 50% marks. "A" means "Absent" and "F" means "Fail".

Sl. No.	Name	Roll No.	Group-I Criminal Law (120 marks)	Group-II Civil Law (120 marks)	Group-B Revenue Law-I & Revenue Law-II (120 marks each 240 marks)	Group-C Accounts (160 marks)	Group-D Constitutional Law (100 marks)	Remarks
1.	Sh. Barinder Thakur	11	—	96(WC)	—	—	—	—
2.	Ms. Aparna Sharma	21	—	—	79 } 162 (HS) 83	—	—	—
3.	Ms. Anuja Sood	31	—	95(WC)	79 } 163 (HS) 84	—	—	—

Sd/-
Superintendent,
Departmental Examination Committee.

SURJIT SINGH,
Secretary.

Shimla-1, the 20th July, 2002

No. HHC/Admn. 3(34)/73-II-14901.—The Hon'ble Chief Justice is pleased to sanction 9 days earned leave w. e. f. 1-8-2002 to 9-8-2002 with permission to suffix Second Saturday and Sunday falling on 10-8-2002 and 11-8-2002 in favour of Shri A. K. Vaidya, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri A. K. Vaidya, Asstt. Registrar is likely to join the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after expiry of above leave period.

Certified that Shri A. K. Vaidya would have continued to officiate on the same post but for his proceeding on leave.

Shimla-1, the 22nd/23rd July, 2002

No. HHC/Admn. Estt./3(80)/75-14976.—The Hon'ble Chief Justice is pleased to sanction *ex-post-facto* 9 days earned leave with effect from 18-6-2002 to 26-6-2002 in favour of Shri K. G. Sharma Court Secretary of this Court.

Certified that Shri K. G. Sharma, Court Secretary has joined the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Certified that Shri K. G. Sharma would have continued to officiate the same post from where he proceeded on leave.

Shimla-1, the 22nd/23rd July, 2002

No. HHC/GAZ/14-199/90-I-15050.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant 9 days earned leave with effect from 29-7-2002 to 6-8-2002 with permission to suffix Sunday falling on 28-7-2002, in favour of Shri S. S. Thakur, Registrar (Vigilance), High Court of Himachal Pradesh Shimla.

Certified that Shri Thakur is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Thakur would have continued to hold the post of Registrar (Vigilance), High Court of Himachal Pradesh Shimla but for his proceeding on leave for the above period.

Shimla-1, the 22nd/23rd July, 2002

No. HHC/GAZ/14-216/95-15040.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant *ex-post-facto* sanction of 3 days commuted leave with effect from 3-7-2002 to 5-7-2002 in favour of Shri Yashwant Singh, Sub-Judge-cum-SDJM, Rajgarh.

Certified that Shri Yashwant Singh has joined the same post and at the same station from where he proceeds on leave after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Yashwant Singh would have continued to hold the post of Sub Judge-cum-SDJM, Rajgarh, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

भाग-2—अधिनियमों को छोड़कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

-गुप्त-

भाग-3—अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, काईनेशियल कमिशनर तथा कमिशनर ऑफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि।

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग (नि०-II)

अधिसूचना

शिमला-171002, 16 जुलाई, 2002

[Authoritative English text of this Department Notification No. Per(AP. B) B (2)-7/99, dated 10-7-2002 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT
(Apptt. II)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th July, 2002

संख्या पर (एपी०बी०) बी (2)-7/99.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी० ई०आर० (एपी०बी०) बी (2)-9/99, तारीख 24-2-2001 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश अधिनियम सेवाएं चयन बोर्ड ने बरिष्ठ सहायक वर्ग-III (भराजपन्नित) के पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 में और संशोधन करने के लिए निम्न लिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधिनियम सेवाएं चयन बोर्ड, बरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (भराजपन्नित) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2002 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध “क” का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश अधिनियम सेवाएं चयन बोर्ड बरिष्ठ सहायक वर्ग-III (भराजपन्नित), भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 के उपाबन्ध “क” में:—

(i) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता”, और

(ii) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपाबन्ध के खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“लिपिकों/कनिष्ठ सहायकों के सामान्य लिपिकीय संवर्ग में से, जिनका 10 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में 31-3-1998 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके उक्त संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सचिवालय/हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य सरकारी विभागों में से इस पद पर समरूप वेतनमान में कार्यरत पदाधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा :

परन्तु यह कि जो लिपिक वर्ग-IV के कर्मचारियों में से प्रोन्नत हुए हैं या कक्षामूलक आधार पर नियुक्त किये गए हैं और जो ऐसी प्रोन्नति/नियुक्ति के समय मैट्रिक पास या मैट्रिक अंग्रेजी के एक विषय सहित रखता हो और हिन्दी रत्न पास शैक्षणिक की अर्हता रखते हो, को बरिष्ठ सहायक के पद पर तब तक प्रोन्नत नहीं किए जाएंगे जब तक कि वे सीधी भर्ती के लिए यथा विहित अनिवार्य अर्हताएं मैट्रिक द्वितीय श्रेणी या 10 जमा 2 पास धारित नहीं कर लेते।

आदेश द्वारा,

हर्ष गुप्ता,
मुख्य सचिव।

No. Per(AP. B) B (2) 7.99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board, Senior Assistant Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2001 notified vide this Department Notification number, Per. (AP. B) B (2)-9/99, dated 24-2-2001, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Technical Services, Recruitment and Promotion Rules (First Amendment) Rules, 2002.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra of Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure “A”.—In Annexure A to the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2001.

(i) For the existing title against Column No. 10, the following shall be substituted, namely:—

“Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various method”; and

(ii) For the existing provisions of clause (i) against Column No. 11, the following shall be substituted, namely:—

“By promotion from amongst the commission clerical cadre of Clerks/Junior Assistants with 10 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* (rendered upto 31-3-1998) service, in the grade failing which by deputation from amongst the incumbents of this posts working in the identical pay scale of this post from H. P. Secretariate/H. P. Public Service Commission /other Government Departments:

Provided that those Clerks who have been promoted from amongst the class-IV employees or appointed on Compassionate grounds having the educational qualification Matric pass or Matric in English only and Hindi Rattan pass at the time of such promotion appointment shall not be promoted to the post of Senior Assistant unless they possess the essential qualification viz. Matric 2nd Division or 10+2 pass as prescribed for direct recruitment.

By order,

HARSH GUPTA,
Chief Secretary.

अधिसूचना

संख्या गृह-बी०(बी०) 2-20/94.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश कारागार विभाग में कनिष्ठ तकनिशियन (कारोन्स्टेबल) वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना में उपावन्ध "क" के अनुसार अर्ही एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं,

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट

दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

[Authoritative english text of this Department's Notification No. Home-B(B)2-20/94, dated 22-5-2002 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd May, 2002

No. Home-B(B) 2-20/94.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Junior Technician (Carpenter Master). Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Prisons, Himachal Pradesh as per Annexure 'A' attached to this notification, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Prisons Department, Junior Technician (Carpenter Master) Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2002.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal and savings.*—(1) The Himachal Pradesh Jails Department, Class-III Subordinate (Non-Gazetted) Services (Recruitment, Promotion and Certain Conditions of Service) Rules, 1967 notified vide this Department's Notification No. H (J) 14-929/58-II, dated 27-11-1967 are hereby repealed to the extent these are applicable to the post of Carpenter Master.

(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed vide rule 2 (1) *supra*, shall be deemed to have validly made, done or taken under these rules.

By order,

R. BHATTACHARYA,
Additional C. S.-cum-Secretary.

ANNEXURE 'A'

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JUNIOR TECHNICIAN (CARPENTER MASTER) CLASS-III (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF PRISONS, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post	Junior Technician (Carpenter Master).
2. Number of posts	2 (Two)
3. Classification	Class-III (Non-Gazetted)
4. Scale of pay	Rs. 3120-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160.
5. Whether selection post or non-selection post.	N. A.
6. Age for direct recruitment.	Between 18 years and 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis or on contract basis had

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षणिक अर्हतायें प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ?

आयु : लागू नहीं
शैक्षणिक अर्हताएं : लागू नहीं

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।

दो वर्ष जिनका एक वर्ष से अधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और निम्नलिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।

शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में, श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जायेगा।

लागू नहीं

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना।

लागू नहीं

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा।

किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर पर नियुक्ति के लिए चयन।

सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

16. आरक्षण

उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किये गये अनुदेशों के अधीन होगी।

17. शिथिल करने की शक्ति

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वहाँ यह कारणों की अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

become coverage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations / Autonomous Bodies shall be allowed with age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who were/are finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the H. P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.

(a) *Essential Qualifications:*

(i) Should have passed Matriculation or its equivalent Examination from a Board of School Education / University recognised by Central/State Government.

(ii) Should also possess Diploma/Certificate in Wood Working from an Institution recognised by the Central/State Government.

(b) *Desirable Qualifications:* Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

ment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

Age : N. A.

Educational Qualifications: N. A.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees?

9. Period of probation, if any.

Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.

100% by direct recruitment.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.

Not applicable

12. If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition.

Not applicable

13. Circumstances under which the H. P. P. S. C. is to be consulted in making recruitment.

As required under the law

14. Essential requirement for direct recruitment.

A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct Recruitment.

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva-voce* test if the H. P. Public Service Commission or Other Recruiting Authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the Commission/Other Recruiting Authority as the case may be.

16. Reservation

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Power to relax

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

श्रम विभाग

शिमला-1, 20 जुलाई, 2002

अधिसूचनाएं

शिमला-1, 20 जुलाई, 2002

संख्या 11-2/93 (लैब 0) आई 0 डी 0 भाग/Nalagarh.—
अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Smt. Raj Rani
w/o Sh. Hari Om, Village Mussewal, P. O. Rajpura, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.)
and the Principal, New Public School, Nalagarh, District Solan (H. P.) के मध्य नीचे दिए
गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4)
के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त
अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के
उपरांत अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि यह मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या
19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 मिनम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधि-
नियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1)
के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक
अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किंये गये विषय पर
अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether the action of termination of services of
Smt. Raj Rani (Peon) w/o Shri Hariom w. e. f.
18-9-2000 without complying the provision of
Industrial Disputes Act, 1947 by the Principal, New
Public School, Nalagarh, District Solan (H. P.)
and then offering part time job is proper and
justified ? If not, what relief of service benefits
the above workman is entitled to ?”

शिमला-1, 20 जुलाई, 2002

संख्या 11-6/85 (लैब 0) आई 0 डी 0 भाग/2002/शिमला.—
अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि श्री नरपत राम पुत्र श्री बजोरू
राम, गांव सहलाना, डाकबोझा शहरोल, तहसील अर्को, जिला सोलन
(हि 0 प्र 0) तथा अधिशासी अभियन्ता, (हि 0 प्र 0) राज्य विद्युत परिषद,
अर्को मण्डल, जिला सोलन, (हि 0 प्र 0) के मध्य नीचे दिये गए
विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4)
के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त
अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने
के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला
श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने योग्य
है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या
19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 मिनम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी, औद्योगिक विवाद
अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा
(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस
मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम-
न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या
किए गए विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है :—

“क्या अधिशासी अभियन्ता, हि 0 प्र 0 राज्य विद्युत परिषद
मण्डल अर्को, जिला सोलन द्वारा श्री नरपत राम पुत्र श्री बजोरू
राम कामगार को वर्ष 1991 से बिना किसी नोटिस, जांच
के तथा क्षतिपूर्ति, मुद्रावजा दिए बिना नौकरी से निकाला
जाना उचित है ? यदि नहीं, तो कामगार किस राहत एवं
सेवा लाभों का हकदार है ?”

संख्या 11-6/85 (लैब 0) आई 0 डी 0 भाग-Shimla.—
अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Molak Ram
s/o Late Sh. Mast Ram, Village Chabaldi, P. O. Gumma, Tehsil and District Shimla, 2. Sh. Lekh
Ram s/o Sh. Uma Dass, Village Pren, P. O. Khera, Tehsil Suni, District. Shimla (H.P.)
and the Executive Engineer, H. P. S. E. B. Division Charli Villa. Shimla (H. P.) के मध्य नीचे दिए
गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4)
के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त
अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के
उपरांत अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने
योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या
19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 मिनम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधि-
नियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1)
के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले
को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/
औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय
पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है :—

1. “Whether the termination of the services of Shri
Molak Ram s/o Late Shri Mast Ram, Ex-daily
wages beldar by the Executive Engineer, H. P.
S.E.B. Division Charli Villa, Shimla (H. P.) w. e. f.
year August 1997 without complying the section
25-F and 25-N of the Industrial Disputes Act, 1947
is proper and justified ? If not, what relief of
service benefits, seniority, backwages and amount
of compensation Shri Molak Ram s/o Late
Shri Mast Ram is entitled to ?”

2. “Whether the termination of the services of Shri
Lekh Ram s/o Sh. Uma Dass, Ex-daily wages
beldar by the Executive Engineer, H. P. S. E. B.
Division Charli Villa, Shimla (H. P.) w. e. f. year
Dec. 1994 without complying the section 25-F and
25-N of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper
and justified ? If not, what relief of service benefits,
seniority, backwages and amount of compensation
Sh. Lekh Ram s/o Sh. Uma Dass is entitled to ?”

शिमला-1, 20 जुलाई, 2002

संख्या 11-6/85 (लैब 0) आई 0 डी 0 भाग-2002-शिमला.—अधो-
हस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Karam Chand s/o
Shri Khayali Ram, Village Gajyali, P. O. Gari,
Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, Himachal
Pradesh and the Divisional Manager, Forest
Working Division Nerwa, Tehsil Chopal, Distt.
Shimla. Himachal Pradesh के मध्य नीचे दिए गए विषय
पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के
अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त
अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के
उपरांत अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि यह मामला श्रम न्यायालय/
औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या
19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 मिनम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,
1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक

अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the retrenchment of services of Shri Karam Chand s/o Shri Khayali Ram w.e.f. 31-12-1992 by the Divisional Manager, Forest Working Division, Nerwa, District Shimla without complying the section 215-N of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits including reinstatement, the above workman is entitled to?"

शिमला-1, 20 जुलाई, 2002

संख्या 11-6/2001 (लैब) आई० डी० भाग Shimla.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Vijay Kumar s/o Shri J. C. Bhardwaj, President AITUC Saproon, District Solan, Himachal Pradesh and The Managing Director M/s Him Teknoforge (Gear Division) Ltd, Village Billanwali, P. O. Baddi, Distt. Solan (H. P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the termination of the Shri Ajay Kumar s/o Shri Amar Nath w.e.f. 23-8-1999 as alleged by the workman under the grab of suspension and neither allowing the worker entry in the gate of factory nor conducting any enquiry and also not paying any subsistence allowance, by the Managing Director, M/s Him Teknoforge (Gear Division) Ltd, Baddi, District Solan is proper and justified? If not, what service benefits, the above workman is entitled to?"

शिमला-1, 20 जुलाई, 2002

संख्या 11-2/93 (लैब०) आई० डी० भाग-Solan.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Babu Lal Ex-Sub-Major, Village and P. O. Subathu, Tehsil Solan (H. P.) and the Principal, Matu Ram Aggarwal D.A.V. Sr. Sec. Public School, Bye Pass, Solan (H. P.) 2. The General Secretary, D.A.V. College Managing Committee, Chitra Gupta Road, New Delhi-1100 055 के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधि-

नियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the retrenchment of Shri Bindu Lal, Ex-Sub Major, Village and P.O. Subathu, Tehsil and District Solan (H.P.) w.e.f. 30-3-2001 as alleged by the Principal, Matu Ram Aggarwal, D.A.V. Sr. Sec. School, Bye Pass Solan, (H. P.) is legal and justified? If not, to what relief Shri Babu Lal is entitled to?"

शिमला-1, 20 जुलाई, 2002

संख्या 11-2/93 (लैब०) आई० डी० भाग-नालागढ़.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Smt. Ram Dulari w/o Shri Satpal, r/o Ward No. 9, Nalagarh, District Solan (H. P.) and M/s Surindera Public Senior Secondary School, Nalagarh, District Solan (H. P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the retrenchment of Smt. Ram Dulari w/o Shri Satpal, Ward No. 9, Nalagarh, District Solan (H. P.) by the Principal, Surindera Senior Secondary Public School, Nalagarh, District Solan (H. P.) w.e.f. 2-6-2001 without complying the provision of section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 is fair and justified? If not, what relief and service benefits, the above worker is entitled to?"

शिमला-1, 20 जुलाई, 2002

संख्या 11-2/93 (लैब०) आई० डी० भाग-परवाणू.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sh. Mahinder Singh s/o Shri Ram Avtar Singh c/o Shri Om Dutt Sharma, Village & P. O. Taksal, Parwanoo, District Solan, (H. P.) 2. Shri Pramod Singh s/o Shri Baijnath Singh, Sector-2, Shop No. 4, Parwanoo, District Solan, (H. P.) 3. Shri Pramod Kumar s/o Shri Trailoki Nath c/o Shri Randhian Singh, Sector-2, Shop No. 4, Parwanoo, District Solan, (H. P.) and the Proprietor/Managing Director, M/s. Kalinga Cables, Plot No. 22, Sector-2, Parwanoo, District Solan, (H. P.) के मध्य नीचे दिये गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिये भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम-न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है:—

“1. Whether the termination of services of Shri Mahinder Singh s/o Shri Ram Avtar Singh and Shri Pramod Singh s/o Shri Baijnath Singh, Daily Wages Operator by the Proprietor/Managing Director, M/s. Kalina Cables, Plot No. 22, Sector-2, Parwaroo w. e. f. 10-11-2000 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation S/Shri Mahinder Singh and Pramod Singh are entitled to?”

“2. Whether the termination of services of Shri Pramod Kumar s/o Shri Trailoki Nath, Daily Wages Accountant by the Proprietor/Managing Director, M/s Kalina Cables, Plot No. 22, Sector-2, Parwanoo, District Solan (H. P.) w. e. f. October, 2000 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation Shri Pramod Kumar is entitled to?”

शिमला-1, 20 जुलाई, 2002

संख्या 11-23/84 (लैब0) आई0 डी0 भाग-Mandi--
अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Parshotam Singh s/o Shri Bihari Lal, Village Dharon Ria, P. O. Matla-Throp, Tehsil Jhanduta, District Bilaspur (H. P.) and the Director of Agriculture (H. P.) Shimla-171 005 के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि यह मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-अम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है:—

“Whether the termination of services of Shri Parshotam Singh s/o Shri Bihari Lal, Ex-daily wages mate by the Director of Agriculture (H. P.), Shimla-171 005 w. e. f. 1-4-1996 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits, backwages, seniority and amount of compensation Shri Parshotam Singh is entitled to?”

शिमला-171001, 22 जुलाई, 2002

संख्या 11-1/85 (लैब0) आई0 डी0 भाग-कांगड़ा.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि श्री अमर नाथ सुपुत्र श्री रत्न चन्द, गांव चननी, डाकखाना भाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा तथा प्रधानाचार्य, इंटरनेशनल संहजा पब्लिक स्कूल, तालनू, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम-न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिये भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-अम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है:—

“क्या श्री अमर नाथ सुपुत्र श्री रत्न चन्द, गांव चननी, डाकखाना भाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा को प्रधानाचार्य इंटरनेशनल संहजा पब्लिक स्कूल, तालनू, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा द्वारा दिनांक 7-8-2001 से विना पूर्व सूचना, नोटिस, मुद्दावजा व कारण बताये वगैर अचानक नौकरी से हटाया जाना उचित व न्याय संगत है? यदि नहीं, तो कामगार श्री अमर नाथ नियोजक से किस राहत व क्षतिपूर्ति का हकदार है?”

हस्ताक्षरित/-
श्रमायुक्त।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 जुलाई, 2002

संख्या मुद्रण (ए) 4-16/93.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 13-8-1997 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में प्लेट मेकर (आफसेट), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, प्लेट मेकर (आफसेट), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2002 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध “अ” का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, प्लेट मेकर (आफसेट), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबन्ध “अ” में:—

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“रुपये 4020-120-4260-140-4400-150-5000-160-5800-200-6200.”

(ख) स्तम्भ संख्या 6 के सामने विद्यमान उपबन्धों में अंकों और शब्दों “18 से 35 वर्ष” के स्थान पर “18 से 45 वर्ष” अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

(ग) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

प्लेट ग्रेनर/डार्क रूम परिचर/फलाई ब्याय (आफसेट) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका 6 वर्ष का नियमित सेवाकाल या 31-3-1998 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित उक्त नियमित सेवाकाल हो और ट्रेड टैस्ट पास किया हो, परन्तु यह

और कि विभाग टैंड टैस्ट की बात अपने नियम बनाएगा और समय-समय पर टैस्ट का संचालन करेगा।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए सभी पात्र कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची उनके सेवाकाल के आधार पर उनके कांडर-बार पारस्परिक बरीयता को छोड़ें बिना तैयार की जाएगी।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-3-1998 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाते के पश्चात् की गई थी। परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-1998 तक तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो निम्नित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो, जो शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पक्ष सम्मने जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिये विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम ग्रहता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जायेगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.— अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिये अपात्र नहीं समझा जायेगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिस पर्सोनल (रिजर्वेशन आफ वेकेंसीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत बरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकेंसीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूज, 1985 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत बरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद पर 31-3-1998 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु 31-3-1998 तक की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक बरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

(घ) स्तम्भ संख्या 14 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।”

आदेश द्वारा,

हरिन्दर हीरा,
प्रधान सचिव।

[Authoritative english text of this Department Notification No. Mudran (A) 4-16/93, dated 18-7-2002 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th July, 2002

No. Mudran (A) 4-16/93.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Printing & Stationery Department, Plate Maker (Offset), Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this Department Notification of even number, dated 13-8-1997, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing & Stationery Department, Plate Maker (Offset), Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2002.

(ii) These Rules shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra (H. P.).

2. *Amendment of Annexure-“A”.*—In Annexure “A” to the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Plate Maker (Offset), Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and promotion Rules, 1997 :—

(a) For existing provisions against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:—

“Rs. 4020-120-4260-140-4400-150-5000-160-5800-200-6200.”

(b) In the existing provisions against Col. No. 6, for the words and figures, “Between 18 and 35 years” the words and figures, “Between 18 and 45 years” shall be substituted.

(c) For existing provisions against Column No. 11, the following shall be substituted, namely:—

“By promotion from amongst the Plate grainer/Dark Room Attendant/Flyboy (Offset) having 6 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* (rendered upto 31-3-1998), service and have passed the trade test. Provided further that the Department frames its rules with regard to Trade test and conduct the tests from time to time.

For the purpose of promotion a combined seniority list of eligible officials on the basis of length of service without disturbing their cadre-wise *inter se* seniority list shall be prepared.

(1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules provided that:—

(i) that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-1998 followed regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less :

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be Ex-serviceman recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R. & P Rules:

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered upto 31-3-1998 as referred to above shall remain unchanged; and

(d) For existing provisions against Column No. 14, the following shall be substituted, namely:—

“A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India”.

By order,

HARINDER HIRA,
Principal Secretary.

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 जुलाई, 2002

संख्या-मुद्रण(ए) 4-14/93.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 24-4-1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में प्लेट ग्रेनर (वर्ग-III अराजपत्रित) के पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, प्लेट ग्रेनर (वर्ग-III अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2002 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपावन्ध “क” का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, प्लेट ग्रेनर (वर्ग-III अराजपत्रित) भर्ती एवं

प्रोन्नति नियम, 1997 के उपावन्ध “क” में:—

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपावन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“रूपरेखा 3120-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160”.

(ख) स्तम्भ संख्या 6 के सामने विद्यमान श्रंकों और शब्दों “18 से 35 वर्ष” के स्थान पर “18 से 45 वर्ष” श्रंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ग) स्तम्भ संख्या 14 के सामने विद्यमान उपावन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्:—

“किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना आवश्यक है।”

मार्देश द्वारा,

हरिन्द्र हीरा,
प्रधान सचिव।

[Authoritative English text of this department notification No. 4-14/93 Mudran, dated 19-7-2002 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19 July, 2002

No. Mudran (A) 4-14/93.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Printing & Stationery Department Plate Grainer, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this Department Notification of even Number dated 24-4-1997, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Plate, Grainer (Class-III, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (1st Amendment) Rules, 2002.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure-“A”.*—In Annexure “A” to the Himachal Pradesh Printing & Stationery Department, Plate Grainer (Class-III Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997:—

(a) For the existing provisions against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:—

“Rs. 3120-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160”.

(b) In the existing provisions against column No. 6 for the words and figures ‘Between 18 and 35 years’ the words and figures, ‘Between 18 and 45 years’ shall be substituted; and

(c) For the existing provision against Col. No. 14 the following shall be substituted namely:—

“A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India”.

By order,

HARINDER HIRA,
Principal Secretary.

भाग-5—वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन

ब अदालत श्री के० एस० पटयाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धुमारवी, जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

व मुकद्दमा :

श्री कृष्णा नन्द पुत्र श्री राम दिता, निवासी चवाड़ी, तहसील
धुमारवी, जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

बनाम

ग्राम जनता

प्रतिवादी ।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण
अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे ।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री कृष्णा नन्द पुत्र राम दिता प्रार्थी ने
दिनांक 8-7-2002 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है
कि मेरा जन्म तिथि 30-12-1944 को हुआ है । लेकिन जन्म तिथि
समय पर ग्राम पंचायत धुमारवी (एन० ए० सी०) में दर्ज नहीं करवाई है,
अब दर्ज करने के आदेश जारी किये जाएं ।

अतः ग्राम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है
कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर/एतराज
आदि हो तो वह पेशी दिनांक 14-8-2002 समय 10.00 बजे
सुबह या इसके पूर्व असासलतन या वकालतन होकर पेश करें अन्यथा
बीगर कार्यवाही एकरफा अमल में लाई जायेगी ।

आज दिनांक 30-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर
अदालत द्वारा जारी हुआ ।

मोहर ।

के० एस० पटयाल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धुमारवी (हि० प्र०) ।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बिझड़ी, उप-तहसील
बिझड़ी, जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

उनवान : इशतहार मकफूद-उल-खबरी ।

श्री हीरा लाल पुत्र श्री लाल सिंह पुत्र सज्जु, वासी टिककर,
तप्पा ढटवाल ।

बनाम

ग्राम जनता

उपरोक्त उनवान मुकद्दमा में श्री हीरा लाल पुत्र लाल सिंह,
वासी टिककर, तप्पा ढटवाल ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये
इशतहार मकफूद उल-खबरी दिया है । जिसमें रिपोर्ट पटवारी भी
ली गई, अनुसार रिपोर्ट हल्का पटवारी श्री भूख पुत्र सज्जु, वासी
टिककर, तप्पा ढटवाल काफी अरसा से लापता है ।

अतः बजरिया इशतहार मकफूद-उल-खबरी सूचित किया जाता
है कि ग्राम जनता को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक
16-8-2002 प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में हाजर आवें ।
यदि भूख पुत्र सज्जु स्वयं भी पढ़े तब उपरोक्त तिथि पर एतराज
पेश कर सकता है इसके उपरान्त कोई भी एतराज नहीं सुना
जायेगा ।

आज दिनांक 12-7-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत
में जारी हुआ ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
ढटवाल (बिझड़ी), जिला हमीरपुर, (हि० प्र०) ।

न्यायालय, श्री सोहन लाल शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल,
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

श्री लाल बहादुर पुत्र राम बहादुर, निवासी गांव अप्पर चूला,
डाकघर बैरछट्टा, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

प्रार्थी ।

बनाम

ग्राम जनता

प्रतिवादी ।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण
अधिनियम, 1969.

चूंकि उपरोक्त वर्णित प्रार्थी ने उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत
अपने पुत्र राजू बहादुर की जन्म तिथि को पंजीकृत करवाने हेतु
अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रकरण दायर किया है । प्रार्थी के
अनुसार उसके पुत्र राजू बहादुर जो कि दिनांक 2-2-1996 को
जन्मा है की जन्म तिथि को वह अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में
पंजीकृत नहीं करवा सका है । अतः अब न्यायालय से आदेश प्राप्त
करके जन्म तिथि को पंजीकृत करवाना चाहता है ।

अतः इस इशतहार के माध्यम से ग्राम व खास जनता को सूचित
किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उपरोक्त
राजू बहादुर की जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह
दिनांक 12-8-2002 को सुबह 10.00 बजे असासलतन या वकालतन
हाजिर होकर अपनी आपत्ति पेश कर सकता है अन्यथा उक्त दिनांक
को किसी भी प्रकार की आपत्ति पेश न होने की दशा में एक-
पक्षीय कार्यवाही प्रतिवादीगण के विरुद्ध अमल में लाई जाकर
आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे ।

आज दिनांक 19-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की
मुद्रिका सहित जारी हुआ ।

मोहर ।

सोहन लाल शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,

थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

न्यायालय श्री सोहन लाल शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री लाल बहादुर पुत्र श्री राम बहादुर, निवासी गांव अप्पर चूला,
डाकघर बैरछट्टा, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

प्रार्थी ।

बनाम

ग्राम जनता

प्रतिवादी ।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण
अधिनियम, 1969.

चूंकि उपरोक्त वर्णित प्रार्थी ने उपरोक्त वर्णित धारा के
अन्तर्गत अपने पुत्र अर्जुन बहादुर की जन्म तिथि को पंजीकृत करने
हेतु अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रकरण दायर किया है । प्रार्थी के
अनुसार उसके पुत्र अर्जुन बहादुर जो कि दिनांक 1-3-1997
को जन्मा है, का जन्म वह अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में
पंजीकृत नहीं करवा सका है । अतः अब न्यायालय से आदेश प्राप्त
करके जन्म तिथि पंजीकृत करवाना चाहता है ।

अतः इस एतद के माध्यम से ग्राम व खास जनता को सूचित
किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उपरोक्त
अर्जुन बहादुर की जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह
दिनांक 12-8-2002 को सुबह 10.00 बजे असासलतन या वकालतन
हाजिर होकर अपनी आपत्ति पेश कर सकता है अन्यथा उक्त दिनांक
को किसी भी प्रकार की आपत्ति पेश न होने की दशा में एक-
पक्षीय कार्यवाही प्रतिवादीगण के विरुद्ध अमल में लाई जाकर
आगामी आदेश पारित कर दिये जायेंगे ।

आज दिनांक 19-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की
मोहर द्वारा जारी हुआ ।

मोहर ।

सोहन लाल शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ।

ब अदालत श्री बी० डी० आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि० प्र०)

व मुकद्दमा:

श्री धन बहादुर पुत्र श्री जू बहादुर

वादी ।

बनाम

ग्राम जनता

प्रतिवादी ।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण
अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम ग्राम जनता ।

श्री धन बहादुर पुत्र श्री जू बहादुर, हाल निवासी गांव दुराह, फाटी
लोट, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू ने इस अदालत में गुजारिश की है कि
प्रार्थी को पुत्री कु० रेवती का जन्म दिनांक 10-4-1996 को पुत्र केसर
बहादुर का जन्म दिनांक 20-3-97, पुत्री सुनीता जन्म दिनांक

12-6-98 को हुआ है। जिनका इन्द्राज पंचायत अभिलेख में न है, अब इन्द्राज किया जावे।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे किसी प्रकार का कोई उजर या आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-8-2002 को इस अदालत में हाजिर आवें अन्यथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को नाम/जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।
बी० डी० आजाद,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड,
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी० डी० आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि० प्र०)

ब मुकद्दमा :

श्री चमन लाल पुत्र श्री भूरा लाल वादी :

बनाम

ग्राम जनता प्रतिवादी।

विषय.— शादी दर्ज करने बारे।

श्री चमन लाल पुत्र भूरा लाल, गांव खलौर, फाटी शहर, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू ने इस अदालत में गुजारिश की है कि प्रार्थी का विवाह दिनांक 10-1-1997 को श्रीमती विद्या देवी पुत्री घनी राम, गांव धार कालना, तहसील डियोग, जिला शिमला के साथ हुआ है जिसका इन्द्राज पंचायत अभिलेख में न है, अब इन्द्राज किया जावे।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे किसी प्रकार का कोई उजर या आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-8-2002 को इस अदालत में हाजिर आवें अन्यथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को नाम/जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।
बी० डी० आजाद,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी० डी० आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि० प्र०)

ब मुकद्दमा :

श्री हरनाम सिंह पुत्र श्री भगत राम वादी।

बनाम

ग्राम जनता प्रतिवादी।

विषय.— श्रीमती शालनी का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे।

श्री हरनाम सिंह पुत्र श्री भगत राम, गांव पुजारली, फाटी निशानी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू ने इस अदालत में गुजारिश की है कि प्रार्थी का विवाह दिनांक 31-1-1998 को श्रीमती शालनी पुत्री भान सिंह निवासी देवधार, तहसील सुन्नी, जिला शिमला के साथ हुआ है। प्रार्थी ने श्रीमती शालनी का नाम पंचायत परिवार रजिस्टर में दर्ज न है, अब दर्ज किया जावे।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे किसी प्रकार का कोई उजर या आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-8-2002 को इस अदालत में हाजिर आवें अन्यथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को नाम/जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।
बी० डी० आजाद,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री बी० डी० आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :—

श्री प्रेम पाल पुत्र उगम राम

वादी।

बनाम

ग्राम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— सही नाम दर्ज करने बारे।

श्री प्रेम पाल पुत्र उगम राम, गांव टिकरी, फाटी असू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू ने इस अदालत में गुजारिश की है कि प्रार्थी की संतान का नाम पंचायत रिकार्ड में क्रमशः कुलदीप चन्द, गोयना देवी, गंगा देवी, गलत दर्ज है जबकि स्कूल रिकार्ड में क्रमशः कुलदीप कुमार, रीता देवी, रीता कुमारी सही दर्ज है प्रार्थी की संतान का सही नाम पुत्र कुलदीप कुमार व दो पुत्रियां रीता देवी, रीता कुमारी का नाम कार्यालय ग्राम पंचायत असू में दर्ज किया जावे।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे किसी प्रकार का कोई उजर या आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-8-2002 को इस अदालत में हाजिर आवें अन्यथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को नाम/जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-6-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।
बी० डी० आजाद,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री बी० डी० आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :—

श्री कर्म दास पुत्र केसी

वादी।

बनाम

ग्राम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— श्री टेक सिंह का नाम दर्ज करने बारे।

श्री कर्म दास पुत्र केसी, गांव पशेरा, फाटी कोटी, तहसील निरमण्ड जिला कुल्लू ने इस अदालत में गुजारिश की है कि प्रार्थी का पुत्र श्री टेक सिंह गलती से प्रार्थी के भाई भादर सिंह के नाम दर्ज है जबकि टेक सिंह प्रार्थी का पुत्र है। श्री टेक सिंह को भादर सिंह के नाम से काट कर प्रार्थी के नाम दर्ज किया जावे।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे किसी प्रकार का कोई उजर या आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-8-2002 को इस अदालत में हाजिर आवें अन्यथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को नाम/जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।
बी० डी० आजाद,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री बी० डी० आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :—

श्री राम रतन पुत्र हर दास

प्रार्थी।

बनाम

ग्राम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— सही नाम दर्ज करने बारे।

श्री राम रतन पुत्र हरदास, गांव खूब, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू ने इस अदालत में गुजारिश की है कि प्रार्थी के पुत्र का नाम बलदेव, ग्राम पंचायत निरमण्ड में त्रुटि पूर्ण दर्ज है जबकि प्रार्थी के पुत्र का सही नाम अभिषेक है। प्रार्थी के पुत्र अभिषेक का नाम ग्राम पंचायत निरमण्ड में दर्ज किया जावे।

अतः इस नोटिस द्वारा ग्राम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे किसी प्रकार का कोई उजर या आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-8-2002 को इस अदालत में हाजिर आवें अन्यथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को नाम/जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

मोहर।

बी० डी० आजाद,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री बी० डी० आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्मा :

श्री प्रेम पाल पुत्र श्री उग्रराम

वादी।

बनाम

ग्राम जनता

प्रतिवादी।

विषय: सही नाम दर्ज करने बारे।

श्री प्रेम पाल पुत्र श्री उग्रराम, गांव टिकरी, फाटी असू; तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू ने इस अदालत में गुजारिश की है कि प्राथी के माता-पिता ने गलती से ग्राम पंचायत असू में प्रेम कुमार वृत्तिपूर्ण लिखवाया है तथा स्कूल रिकार्ड में प्राथी का नाम प्रेम पाल दर्ज है प्राथी का नाम कार्यालय ग्राम पंचायत असू में भी प्रेम पाल दर्ज किया जावे।

अतः इस नोटिस द्वारा ग्राम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे किसी प्रकार का कोई उजर या आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-8-2002 को इस अदालत में हाजिर आवें अन्यथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को नाम/जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

बी० डी० आजाद,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री बी० डी० आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्मा :

श्री निरमू राम पुत्र श्री फिगडू राम

वादी।

बनाम

ग्राम जनता

प्रतिवादी।

विषय: सही नाम दर्ज करने बारे।

श्री जिगमू राम पुत्र श्री फिगडू, गांव खेखा, फाटी देखा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू ने इस अदालत में गुजारिश की है कि प्राथी के पुत्र पूत लाल का नाम कार्यालय कोट में गलत दर्ज है जबकि प्राथी के पुत्र का नाम ताशन देव सही व दस्त है कार्यालय ग्राम पंचायत कोट में ताशन दर्ज किया जावे।

अतः इस नोटिस द्वारा ग्राम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे किसी प्रकार का कोई उजर या आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-8-2002 को इस अदालत में हाजिर आवें अन्यथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को नाम/जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

बी० डी० आजाद,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री बी० डी० आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि० प्र०)

ब मुकद्मा :

श्रीमती लक्षा देवी पत्नी धन सिंह

वादी।

बनाम

ग्राम जनता

प्रतिवादी।

विषय: ग्राम पंचायत निशानी में नाम दर्ज करने बारे।

श्रीमती लक्षा देवी पत्नी श्री धन सिंह, गांव व फाटी निशानी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू ने इस अदालत में गुजारिश की है कि प्राथिनी अपने परिवार समेत ग्राम पंचायत निशानी में रहती है। प्राथिनी की सन्तान ग्राम पंचायत निशानी में दर्ज है तथा प्राथिनी व प्राथिनी के पति का नाम परिवार रजिस्टर में भूल के कारण दर्ज नहीं हुए हैं। लक्षा देवी पत्नी धन सिंह व श्री धन सिंह पुत्र श्री विशवा राम का नाम ग्राम पंचायत निशानी में दर्ज किया जावे।

अतः इस नोटिस द्वारा ग्राम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर इस बारे किसी को कोई उजर या आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-8-2002 को इस अदालत में हाजिर आवें अन्यथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

बी० डी० आजाद,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री बी० डी० आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्मा :

श्री भीके राम पुत्र श्री भगत राम

वादी।

बनाम

ग्राम जनता

प्रतिवादी।

विषय: श्रीमती सैतू देवी का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे।

श्री भीके राम पुत्र श्री भगत राम, गांव व फाटी त्वार, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू ने इस अदालत में गुजारिश की है कि प्राथी की पत्नी श्रीमती सैतू देवी का नाम ग्राम पंचायत निशानी में प्राथी के भाई अनूप राम के नाम पत्नी के रूप में दर्ज है, जो वृत्तिपूर्ण है। श्रीमती सैतू देवी प्राथी की पत्नी है जिसका नाम ग्राम पंचायत निशानी परिवार रजिस्टर में प्राथी के नाम दर्ज किया जावे।

अतः इस नोटिस द्वारा ग्राम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे किसी प्रकार का कोई उजर या आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-8-2002 को इस अदालत में हाजिर आवें अन्यथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को नाम/जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

बी० डी० आजाद,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी० डी० आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

नाम परिवर्तन

ब मुकदमा :

श्री विजय राम पुत्र श्री डेन्डी राम

..वादी ।

बनाम

ग्राम जनता

..प्रतिवादी ।

विषय.—श्रीमती ऊषा देवी का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे ।

श्री विजय राम पुत्र श्री डेन्डी राम, गांव डोली नाल फाटी त्वार, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू ने इस अदालत में गुजारिश की है कि प्रार्थी का विवाह श्रीमती ऊषा देवी पुत्री श्री भगत राम, गांव डावर, फाटी लोट, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू के साथ हुआ है प्रार्थी ने गलती से उक्त पत्नी का नाम परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत निशानी में दर्ज न की, है अब दर्ज किया जावे ।

अतः इस नोटिस द्वारा ग्राम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे किसी प्रकार का कोई उजर या आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-8-2002 को इस अदालत में हाजिर आवें अन्यथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को नाम/जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे ।

आज दिनांक 13-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ ।

मोहर ।

बी० डी० आजाद,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री बी० डी० आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

ब मुकदमा :

श्री विशन देव पुत्र श्री पुष्प राम

..वादी ।

बनाम

ग्राम जनता

..प्रतिवादी ।

विषय.—यशपाल का नाम परिवार रजिस्टर से काटने बारे ।

श्री विशन देव पुत्र श्री पुष्प राम, गांव फाटी गाड़ शौहच, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू ने इस अदालत में गुजारिश की है कि प्रार्थी के तीन पुत्रान सर्वश्री हेम राज, राजीव व लायक राम है तथा अन्य कोई पुत्र न है प्रार्थी के नाम यशपाल भी दर्ज है जबकि प्रार्थी का पुत्र नहीं है प्रार्थी का नाम गलती से लिखा गया यशपाल पुत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कार्यालय असू से काट दिया जावे ।

अतः इस नोटिस द्वारा ग्राम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे किसी प्रकार का कोई उजर या आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-8-2002 को इस अदालत में हाजिर आवें अन्यथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को नाम/जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे ।

आज दिनांक 13-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ ।

मोहर ।

बी० डी० आजाद,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि० प्र०) ।

नाम परिवर्तन

मै, सोनम डोलमा पत्नी श्री जूरमेद, गांव व कोठी कारदंग, जिला लाहौल स्पीति (हि० प्र०) ने अपना नाम बदल कर लीना रख लिया है। भविष्य में मुझे लीना नाम से जाना जाए।

लीना,

गांव कोठी कारदंग,

जिला लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश ।

मै, जूरमेद पुत्र श्री छेरिंग टशी, गांव व कोठी कारदंग, जिला लाहौल स्पीति (हि० प्र०) ने अपना नाम बदल कर सुशील कुमार रख लिया है भविष्य में मुझे सुशील कुमार नाम से जाना जाए ।

सुशील कुमार,

गांव व कोठी कारदंग,

जिला लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री शिव देव सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दर-नगर, जिला मण्डी (हि० प्र०)

ब मुकदमा :

सोनू पुत्र सन्त राम, निवासी दुन, इलाका भगाहल वजरिया नरोतम पुत्र खिप दास, निवासी हानग, ईलाका गुम्मा ठान, तहसील जोगिन्दर नगर

.. प्रार्थी ।

बनाम

ग्राम जनता

.. प्रत्यार्थी ।

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके दोहते सोनू का जन्म दिनांक 4-3-1996 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, अब दर्ज करने के आदेश जारी किया जावे ।

अतः इस इशतहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा ग्राम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे में किसी को उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-8-2002 को सुबह 10 बजे असालतन या बकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत कर सकता है बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा सोनू को जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिये जायेंगे ।

आज दिनांक 15-7-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ ।

मोहर ।

शिव देव सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि० प्र०) ।

ब अदालत श्री शिव देव सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी (हि० प्र०)

ब मुकदमा :

श्रीमती आशा राठीर पत्नी श्री बलविन्द्र सिंह, निवासी दुन, तहसील जोगिन्दर नगर

.. प्रार्थी ।

बनाम

ग्राम जनता

.. प्रत्यार्थी ।

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पुत्र क्षतिज का नाम सम्बन्धित पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं है। क्षतिज का जन्म दिनांक 20-3-2001 को हुआ था और नाम अब दर्ज करने के आदेश जारी किये जायें ।

अतः इस इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा ग्राम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे में किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 12-8-02 को सुबह 10.00 बजे असालतन या बकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा क्षतिज की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिये जायेंगे ।

आज दिनांक 15-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

शिव देव सिंह,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि० प्र०)

नाम दावा : दस्तूरी नाम

ब मुकद्दमा :

श्री स्वर्ण कुमार उर्फ सवर्ण सिंह पुत्र रोशन लाल, निवासी खियूरी, डा० राजगढ़

बनाम

ग्राम जनता

प्रत्यार्थी ।

प्रार्थना-पत्र बाबत दस्तूरी नाम ।

उपरोक्त मुकद्दमा में ग्राम जनता को इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर आपको नाम की दस्तूरी बारा किसी किस्म का कोई एतराज हो तो वह दिनांक 14-8-02 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा आपके हाजिर न आने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

आज दिनांक 15-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/-,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जिला मण्डी (हि० प्र०) ।

ब अदालत श्री बलदेव ठाकुर, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री चेत राम पुत्र श्री सोजू राम, निवासी रडू, डाकखाना जुगाहन, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी ।

बनाम

ग्राम जनता

प्रतिवादी ।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारा ।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री चेत राम प्रार्थी ने दिनांक 25-6-2002 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 10-3-1959 को उसके निवास स्थान पर हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत कनेड में उसकी जन्म तिथि सिर्फ सन् 1956 दर्ज है, जो कि गलत दर्ज है । सही जन्म तिथि 10-3-1959 को दर्ज करने के आदेश जारी किए जावें ।

अतः ग्राम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा उजर व एतराज आदि हो तो वह पेशी दिनांक 14-8-2002 समय 10.00 बजे सुबह या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 1-7-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

बलदेव ठाकुर,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि० प्र०) ।

ब अदालत श्री बलदेव ठाकुर, स्पेशल मैरीज अधिकारी (एस० डी० एम०), सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

1. श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री दीवान चन्द, निवासी देहरा, डाकखाना सुन्दरनगर नं० 1, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि० प्र०) ।
2. सोनिया गुप्ता पुत्री श्री दिनेश कुमार गुप्ता, निवासी लछमी निवास, सुजानपुर टीहरा, जिला हमीरपुर (हि० प्र०) प्रार्थीगण ।

बनाम

ग्राम जनता

प्रतिवादी ।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15 स्पेशल मैरीज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे ।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री जितेन्द्र कुमार व सोनिया गुप्ता प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 6-7-2002 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 2-7-2002 को माहाया मन्दिर, सुन्दरनगर में हिन्दु रीति-रिवाज के अनुसार शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं । जेर धारा 15 स्पेशल मैरीज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजीकृत किया जावे ।

अतः ग्राम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है, कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई एतराज आदि हो तो वह पेशी दिनांक 7-8-2002 समय 10.00 बजे सुबह या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 6-7-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

बलदेव ठाकुर,
स्पेशल मैरीज अधिकारी, (एस० डी० एम०)
सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ।

कार्यालय श्री के० डी० प्रेमी, कार्यकारी दण्डाधिकारी शिलाई, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

टीका राम पुत्र मनिया, ग्राम नाया, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ।

बनाम

ग्राम जनता

प्रतिवादी ।

दावा.—दरखास्त बराये दुरुस्ती पंचायत अभिलेख ।

नोटिस वनाम ग्राम जनता ।

श्री टीका राम पुत्र मनिया, ग्राम नाया, तहसील शिलाई ने इस कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि श्रीमती चमको देवी सायल की धर्म पत्नी है । और चमको देवी के तुल्यम से तीन बच्चे क्रमशः रविन्द्र सिंह, रोहित पुत्रान व कुमारी प्रियंका पुत्री सायल के हैं परन्तु पंचायत अभिलेख में श्रीमती चमको देवी पत्नी दीप राम व मिस्टर रविन्द्र सिंह पुत्र दीप राम दर्ज है । गो कि गलती से छोटे भाई के नाम दर्ज हुए हैं, कृपया पंचायत अभिलेख में सायल के नाम दुरुस्त किये जावें ।

अतः इस नोटिस द्वारा ग्राम जनता व सम्बन्धित रिस्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 5-8-2002 से पूर्व इस कार्यालय अपना एतराज पेश करें, अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को अभिलेख दुरुस्त करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

आज दिनांक 15-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर ।

के० डी० प्रेमी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शिलाई, जिला सिरमौर, (हि० प्र०) ।

कार्यालय श्री के० डी० प्रेमी, कार्यकारी दण्डाधिकारी शिलाई, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

ब अदालत श्री टी० जी० नेगी, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

कुन्दन सिंह पुत्र मीना, ग्राम ब्यारका, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि० प्र०) । वादी ।

श्रीमती गंगा देई बेवा मथरा राम, निवासी गांव मेरी, तहसील अर्की, जिला सोलन (हि० प्र०) ।

बनाम

बनाम

ग्राम जनता

प्रतिवादी ।

दावा.— दहस्ती पंचायती अभिलेख ।

ग्राम जनता

नोटिस बनाम ग्राम जनता ।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कुन्दन सिंह पुत्र मीना, ग्राम ब्यारका, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि सायल ने श्रीमती मनसो देवी पुत्री नानक, ग्राम बान्दली से हुई है और श्रीमती मनसो देवी के पास एक लड़का पैदा हुआ है जिसका नाम धनवीर है और धनवीर की जन्म तिथि 6-7-1998 है । परन्तु गलती से श्रीमती मनसो देवी व पुत्र धनवीर की जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है । अब उन्हें दर्ज करने के आदेश दिये जावें ।

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके बच्चों 1. कुमारी सुनिता पुत्री का जन्म 14-10-1996, 2. मोनू पुत्र का जन्म 13-11-1999, 3. रीना देवी पुत्री का जन्म 1-1-2001 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत सायल के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, अब दर्ज करने के आदेश जारी किये जावें ।

अतः इस नोटिस द्वारा ग्राम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 15-8-2002 से पूर्व इस कार्यालय में प्रेषित करें अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को अभिलेख दहस्त करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

अतः इस इशतहार राजपल, हिमाचल प्रदेश द्वारा ग्राम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 12-8-2002 को सुबह 10.00 बजे असालतन या बकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत कर सकता है । बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा जन्म तिथियां पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे ।

आज दिनांक 22-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

आज दिनांक 9-7-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । के० डी० प्रेमी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शिलाई, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ।

न्यायालय श्री के० डी० प्रेमी, कार्यकारी दण्डाधिकारी शिलाई, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

मोहर । टी० जी० नेगी, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, अर्की, जिला सोलन (हि० प्र०) ।

श्रीमती हीरा देवी पुत्री कालिया, ग्राम खडेच, सब-तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि० प्र०) वादी ।

ब अदालत श्री अवनीश शर्मा, नायब तहसीलदार व अखत्यार सहायक कुलेक्टर द्वितीय श्रेणी, भरवाई, जिला ऊना

बनाम ग्राम जनता प्रतिवादी ।

दरखवास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

रमेश कुमार पुत्र श्रींकार चन्द पुत्र गुरदास, वासी गांव नारी, उप-तहसील भरवाई, जिला ऊना (हि० प्र०) प्रार्थी ।

नोटिस बनाम ग्राम जनता ।

विषय.—दरखवास्त बराये दहस्ती नाम राजस्व रिकार्ड हेतु ।

श्रीमती हीरा देवी पुत्री कालिया, ग्राम खडेच, सब-तहसील शिलाई, जिला सिरमौर ने इस कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके लड़के रणजीत सिंह की जन्म तिथि 26-12-1997 है । परन्तु गलती से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है और प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि पंचायत को लड़के की जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी किये जावें ।

अतः इस नोटिस द्वारा ग्राम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 15-8-2002 से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

आज दिनांक 6-7-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

आज दिनांक 22-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर । के० डी० प्रेमी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ।

मोहर । अवनीश शर्मा, नायब तहसीलदार, भरवाई, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

भाग 6—भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन

LAW DEPARTMENT
(Legislation)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th January, 2001

No. L. L. R-E(9)-2/2000-Leg-II.—The following ordinance, promulgated by the president of India in the Gazette of India, Extra-ordinary, part-II, Section-I is hereby republished in the Himachal Pradesh, Rajpatra for the information of the general public.

Sl. No.	Title	Date of the Gazette of India in which the ordinance published.
1	2	3
1.	The Indian Council of World Affairs Ordinance 2001 (Ordinance No. 1 of 2001).	05-01-2001

By order,
Sd/-
Secretary (Law).

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY
AFFAIRS

(Legislative Department)

New Delhi, the 5th January, 2001/Pousa 15, 1922 (Saka)

THE INDIAN COUNCIL OF WORLD AFFAIRS
ORDINANCE, 2001

(No. 1 OF 2001)

Promulgated by the President in the Fifty-first Year of the Republic of India.

An Ordinance to declare the Indian Council of World Affairs to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and matters connected therewith.

WHEREAS the Indian Council of World Affairs Ordinance 2000, to provide for the aforesaid matters was promulgated by the President on the 1st day of September, 2000.

AND WHEREAS, the Indian Council of World Affairs Bill, 2000, to replace the said Ordinance has been passed by the House of the People and is pending in the Council of States;

AND WHEREAS the Indian Council of World Affairs Ordinance, 2000 ceased to operate on the 1st day of January, 2001;

AND WHEREAS, it is considered necessary to give continued effect to the provisions of the Indian Council of World Affairs Ordinance, 2000 and to validate the actions taken under the said Ordinance.

AND WHEREAS Parliament is not in session and the president is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. *Short title and commencement.*—(1) This Ordinance may be called the Indian Council of World Affairs Ordinance, 2001.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of September, 2000.

2. *Declaration of the Indian Council of World Affairs as institution of national importance.*—Whereas the object of the Indian Council of World Affairs, a society under the Societies Registration Act, 1860 are such as to make the institution one of national importance, it is hereby declared the institution, known as the Indian Council of World Affairs, is an institution of national importance.

3. *Definition.*—In this Ordinance, unless the context otherwise requires,—

- (a) "appointed day" means the date of commencement of this Ordinance;
- (b) "Chairperson" means the Chairperson of the Governing Body;
- (c) "Council" means the Indian Council of World Affairs incorporated under section 4;
- (d) "Director-General" means the Director-General of the Council;
- (e) "existing Council" means the Indian Council World Affairs, a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), and functioning as such immediately before the appointed day;
- (f) "Fund" means the Fund of the Council referred to in section 18;
- (g) "Governing Body" means the Governing Body of the Council;
- (h) "member" means a member of the Council and includes the President and Vice-President;
- (i) "President" means the President of the Council;
- (j) "regulation" means the regulations made under this Ordinance;
- (k) "rules" means the regulations made under this Ordinance ;
- (l) "Vice-President" means the Vice-President of the Council.

4. *Incorporation of the Council.*—(1) The Indian Council of World Affairs is hereby constituted a body corporate by the name of the Indian Council of World Affairs and as such body corporate it shall have perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Ordinance, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and shall by that name sue and be sued.

(2) The head office of the Council shall be at Delhi and the Council may, with the previous approval of the Central Government, establish branches at other places in India,

5. *Transfer of assets and liabilities of existing Council to the Council.*—(1)—On and from the appointed day,—

- (a) all properties and other assets vested in the existing Council immediately before that day, shall vest in the Council;
- (b) all debts, obligations and liabilities incurred, all contracts entered into and all matters and things engaged to be done by, with or for the existing Council immediately before that day for or in connection with the purposes of the existing Council, shall be deemed to have been incurred entered into and engaged to be done by, with or for the Council;
- (c) all sums of money due to the existing Council, immediately before that day, shall be deemed to be due to the Council;
- (d) all suits and other legal proceedings instituted or which could have been instituted by or against Council, immediately before that day, may be continued or instituted by or against the Council; and
- (e) every employee holding any office under the existing Council immediately before that day, shall, on that day, hold his office of service under the Council with the same rights and privileges as to person, gratuity and other matters as would

have been admissible to him if there had been no such vesting ; and shall constitute to do so unless and until his employment under the council is duly terminated or until his remuneration and other conditions of service are duly altered by the council.

(2) Notwithstanding anything contained in the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), or in any other law for the time being in force, the absorption of any employee by the Council in its regular service under this section shall not entitle such employee to any compensation under that Act or any other law and no such claim shall be entertained by any court, tribunal or other authority.

6. Obligation to transfer property or assets.—(1) Every person having possession, custody or control of property forming part of the properties and other assets referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 5 shall delivery forthwith such property to the Director General.

(2) Any person incharge of the property and other assets of the existing Council immediately before the commencement of this Ordinance shall, within ten days from that day furnish to the Director-General complete inventory of all properties and assets (including particulars of book debts and investments and belongings) immediately before the commencement of this Ordinance and also of all agreements entered into by the existing Council or any person on its behalf.

7. Composition of the Council.—(1) The Council shall consist of the following members, namely:—

- (a) the Union Minister for External Affairs who shall be the President, *ex officio*;
- (b) a Vice-President, who shall be elected by the Council from amongst its members ;
- (c) a Director-General, who shall be appointed by the Central Government ;
- (d) three members to be nominated by the Central Government who are distinguished in the field of diplomacy, international affairs and law;
- (e) four members to be nominated by the Central Government from amongst experts in the fields of history, economics, security studies and social sciences ;
- (f) two members to be nominated by the Central Government from amongst the Vice-Chancellors of Universities; and
- (g) four members to be nominated by the Council.

(2) It is hereby declared that the office of the member of the Council shall not disqualify its holder for being chosen as, or for being, a Member of either House of Parliament.

(3) A person shall be disqualified for being nominated as a member if he :—

- (a) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or
- (b) is an undischarged insolvent ; or
- (c) is of unsound mind and stands so declared by a competent court.

8. Term of office and vacancies, among members.—(1) Save as otherwise provided in this section, the term of office of a member shall be three years from the date of his nomination.

(2) The terms of office of the members nominated to fill a casual vacancy shall continue for remainder of the term in whose place he is nominated.

(3) A member shall, unless the Central Government otherwise directs, continue in office until another person is nominated as a member in his place.

(4) The Central Government shall remove a member if he:—

- (a) becomes subject to any of the disqualifications mentioned in sub-section (3) of section 7 ; or
- (b) refuses to act or becomes incapable of acting; or
- (c) is, without obtaining leave of absence from the Council, absent from three consecutive meetings of the Council ; or
- (d) in the opinion of the Central Government, has so abused his position as to render his continuance in office detrimental to the public interest.

Provided that no member shall be removed under this clause unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(5) A member shall, unless disqualified under sub-section (3) of section 7, be eligible for re-nomination.

(6) A member may resign his office by writing under his hand addressed to the Central Government but shall continue in his office until his resignation is accepted by that Government.

(7) The manner of filling vacancies among members shall be such as may be prescribed by rules.

9. Powers and functions of President.—The President shall exercise such powers and discharge such functions as are laid down in this ordinance or as may be prescribed by rules.

10. Powers and functions of Vice-President.—The Vice-President shall exercise such of the powers and perform such of the functions of the President as may be prescribed by rules or as may be delegated to him by the President.

11. Allowances of Members.—Members shall receive such allowances, if any, from the Council as may be prescribed by rules.

12. Meetings of Council.—The Council shall hold its meeting at such time and place as may be appointed by the Central Government and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at the first meeting as may be laid down by that Government and thereafter the Council shall meet at such times and places and observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings as may be prescribed by regulations.

13. Objects of Council.—The objects of the Council shall be:—

- (a) to promote the study of Indian and international affairs so as to develop a body of informed opinion on international matters;
- (b) to promote India's relations with other countries through study, research, discussion, lectures, exchange of ideas and information with other organisations within and outside India engaged in similar activities;
- (c) to serve as a clearing house of information and knowledge regarding world affairs ;
- (d) to publish books, periodicals, journals, reviews, papers, pamphlets and other literature on subjects covered under clause (a) and (b) ;
- (e) to establish contacts with organisations promoting objects mentioned in this section ;
- (f) to arrange conferences and seminars to discuss and study the Indian policy towards international affairs ; and
- (g) to undertake such other activities for the promotion of ideas and attainment of the above mentioned objects.

14. Governing Body and other committees of Council.—

(1) There shall be a Governing Body of the Council which shall be constituted by the Council from amongst its members in such manner as may be prescribed

by regulations.

(2) The Governing Body shall be the executive Committee of the Council and shall exercise such powers and discharge such functions as the Council may, by regulations made in this behalf, confer or impose upon it.

(3) The President shall be the Chairperson of the Governing Body and as chairperson thereof shall exercise such powers and discharge such functions as may be prescribed by regulations.

(4) The procedure to be followed by the Governing Body in the exercise of its powers and discharge of its functions and the term of office of and the manner of filling vacancies among the members of, the Governing Body, shall be such as may be prescribed by regulations.

(5) Subject to such control and restrictions as may be prescribed by rules, the Council may constitute as many standing committees and as many *ad hoc* committees as it think fit for exercising any power or discharging any function of the Council or for inquiring into, or reporting or advising upon, any matter which the Council may refer to them.

(6) The Chairperson and members of the Governing Body or a standing committee or an *ad hoc* committee shall receive such allowances as may be prescribed by regulations.

15. *Staff of Council.*—(1) There shall be chief executive officer of the Council who shall be designated as the Director-General and shall be appointed by the Ministry of External Affairs.

(2) The Director-General shall act as the Secretary to the Council as well as to the Governing Body.

(3) The Director-General shall exercise such powers and discharge such functions as may be prescribed by regulations or as may be delegated to him by the Council or the President or the Governing Body or the Chairperson.

(4) The Financial Advisor of the Ministry of External Affairs shall be the Financial Advisor of the Council.

(5) Subject to such rules as may be made in this behalf, the Council may appoint such number of other officers and employees as may be necessary for the exercise of its powers and efficient discharge of its functions and may determine the designations and grades of such other officers and employees.

(6) Subject to such rules as may be made in this behalf, the Director-General and other officers and employees of the Council shall be entitled to such salary and allowances and shall be governed by such conditions of service in respect of leave, pension, gratuity, provident fund and other matters, as may be prescribed by regulations made in this behalf.

16. *Functions of Council.*—The Council shall undertake various plans to promote, organise and implement various programmes for efficiently achieving the objects of the Council specified in section 13 and shall also perform such other functions as the Central Government may, by rules, prescribe.

17. *Payment to Council.*—The Central Government may after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, pay to the Council in each financial year such sums as may be considered necessary for the exercise of powers and efficient discharge of functions of the Council under this Ordinance.

18. *Fund of Council.*—(1) The Council shall maintain a Fund to which shall be credited.—

(a) all moneys received from the Central Government;

(b) all moneys received by the Council by way of grants, gifts, donations, benefactions, bequests or transfers; and

(c) all moneys received by the Council in any other manner or from any other source.

(2) All moneys credited to the Fund shall be deposited in such banks or invested in such manner as the Council may, subject to the approval of the Central Government, decide.

(3) The Fund shall be applied towards meeting the administrative and other expenses of the Council, including expenses incurred in the exercise of its powers and discharge of its functions under section 16 or in relation to any of the activities referred to therein or for anything relatable thereto.

19. *Budget of Council.*—The Council shall prepare, in such form and at such time every year, as may be prescribed by rules, a budget in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts and expenditure of the Council and shall forward to the Government such number of copies thereof as may be prescribed by rules.

20. *Accounts and Audit.*—(1) The Council shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the balance-sheet in such form as the Central Government may, by rules, prescribe and in accordance with such general direction as may be issued by that Government, in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

(2) The accounts of the Council shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India and any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable by the Council to the Comptroller and Auditor-General of India.

(3) The Comptroller and Auditor General of India and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Council shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General of India has in connection with the audit of the Government accounts and in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect the office or offices of the Council.

(4) The accounts of the Council certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf, together with the audit report thereon, shall be forwarded annually to the Central Government and that Government shall cause the same to be laid before each House of Parliament.

21. *Annual report.*—The Council shall prepare every year, in such form and at such time as may be prescribed by rules, an annual report giving a true and full account of its activities during the previous year and copies thereof shall be forwarded to the Central Government and that Government shall cause the same to be laid before each House of Parliament.

22. *Authentication of orders instruments of Council.*—All orders and decisions of the Council shall be authenticated by the signature of the President or the Vice-President and all other instruments issued by the Council shall be authenticated by the signature of the Director General or any other officer of the Council authorised by the Council in this behalf.

23. *Vacancy, etc. not to invalidate proceedings of the Council, etc.*—No act or proceeding of the Council, Governing Body or any standing or *ad hoc* committee under this Ordinance shall be invalid merely by reason of—

(a) any vacancy in, or any defect in the constitution of the Council; or

- (b) any defect in the appointment of a person acting as a member of the Council; or
- (c) any irregularity in the procedure of the Council not affecting the merits of the case.

24. Reports, returns and information.—The Council shall furnish to the Central Government such reports, returns and other information as that Government may require from time to time.

25. Power to make rules.—(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Ordinance.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the manner of filling vacancies among members under sub-section (7) of section 8 ;
- (b) the powers and functions to be exercised and discharged by the President and the Vice-President under section 9 and 10, as the case may be;
- (c) the allowances to be paid to the members under section 11 ;
- (d) the control and restrictions in relation to the constitution of standing and *ad hoc* committees under sub-section (5) of section 14 ;
- (e) the number of other officers and employees that may be appointed by the Council and the manner of such appointment under sub-section (5) of section 15 ;
- (f) the salaries and allowances payable to the Director General and other officers and employees of the Council under sub-section (6) of section 15 ;
- (g) such other functions to be performed by the Council under section 16 ;
- (h) the form in which and the time at which the budget shall be prepared by the Council and the number of copies thereof to be forwarded to the Central Government under section 19 ;
- (i) the form in which an annual statement of accounts including the balance-sheet shall be prepared by the Council under sub-section (1) of section 20 ;
- (j) the form in which and the time at which the annual report of the activities of the Council shall be submitted to the Central Government under section 21 ;
- (k) any other matter which has to be or may be prescribed by rules.

26. Power to make regulations.—(1) The Council may, with the previous approval of the Central Government, make regulations consistent with the provisions of this Ordinance and the rules to carry out the provisions of this Ordinance.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the summoning and holding of meetings, other than the first meeting of the Council the time and place where such meetings are to be held and the transaction of business at such meetings under section 12 ;
- (b) the manner in which the Governing Body shall be constituted under sub-section (1) of section 14 ;
- (c) the powers and functions to be exercised and discharged by the Governing Body and the Chairperson under sub-section (2) and (3) of section 14 ;
- (d) the procedure to be followed by the Governing Body in exercise of its powers and discharge of its functions and the term of office of, and the

manner of filling vacancies among, the members of the Governing Body under sub-section (4) of section 14 ;

- (e) the allowances to be paid to the members of the standing and *ad hoc* committees under sub-section (6) of section 14 ;
- (f) the powers and functions to be exercised and discharged by the Director General under sub-section (3) of section 15 ;
- (g) the conditions of service of the Director General and other officers and employees of the Council under sub-section (6) of section 15 ;
- (h) any other matter which has to be or may be prescribed by regulations.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the first regulations under this Ordinance shall be made by the Central Government and any regulations so made may be altered or rescinded by the Council in exercise of its powers under sub-section (1).

27. Rules and Regulations to be laid before Parliament.—Every rule and every regulation made under this Ordinance shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or regulation or both Houses agree that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation.

28. Power to Remove Difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this ordinance as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the promulgation of this Ordinance.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament.

29. Validation and savings.—Notwithstanding the fact that the Indian Council of World Affairs Ordinance, 2000 (ord. 3 of 2000), has ceased to operate, it shall not affect.—

- (a) the previous operation of, or anything duly done or suffered under the provisions of the Indian Council of World Affairs Ordinance, 2000 (Ord. 3 of 2000), (hereinafter referred to as "the Ordinance");
- (b) any right privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Ordinance;
- (c) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any right, privilege obligation or liability as aforesaid;

and any such investigation legal proceeding or remedy may be instituted, continued or

Council of World Affairs Ordinance, 2001 had been in force at all material times.

K. R. NARAYANAN.
President.

SUBHASH C. JAIN
Secy. to the Government of India.

LAW DEPARTMENT
(Legislation)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th February, 2001

No. LLR-E (9)-2/2000-Leg.-II.—The following ordinance, promulgated by the president of India in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, Section-I is hereby republished in the Himachal Pradesh Rajpatra for the information of the general public.

Sl. No.	Titale	Date of the Gazette of India in which the ordinance published
1.	The Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2001 (Ordinance No. 2 of 2001).	3-2-2001

By order,

Sd/-
Secretary.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

New Delhi, the 3rd February, 2001/Magha 14, 1922 (Saka)

THE TAXATION LAWS (AMENDMENT) ORDINANCE, 2001

No. 2 of 2001

Promulgated by the President in the Fifty-second Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Finance Act, 2000 and the Income Tax Act, 1961.

Whereas Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2001.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2 of Finance Act, 2000.—In section 2 of the Finance Act, 2000 (10 of 2000) (hereinafter referred to as the principal Act),—

(a) in sub-section (4),—

(i) in clause (a), for the words “ten per cent” the words “twelve per cent” shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the words “eleven per cent”, the words “thirteen per cent” shall be substituted,

(b) in sub-section (6),—

(i) in clause (a), for the words “ten per cent”, the words “twelve per cent” shall be substituted ;

(ii) in clause (b), for the words “eleven per cent”, the words “thirteen per cent.” shall be substituted.

(c) in sub-section (7),—

(i) in clause (a), for the words “ten per cent.” the words “twelve per cent” shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the words “eleven per cent”, the words “thirteen per cent.” shall be substituted.

(d) in sub-section (8), in the third proviso, in clause (a),—

(i) in sub-clause (i) for the words “ten per cent”, the words “twelve per cent” shall be substituted ;

(ii) in sub-clause (ii),—

(A) in item (A), for the words “ten per cent.”, the words “twelve per cent.”, shall be substituted ;

(B) in item (B), for the words “fifteen per cent.”, the words “seventeen per cent.” shall be substituted.

(e) in sub-section (8), in the third proviso, in clause (b), for the words “eleven per cent.”, the words “thirteen per cent.” shall be substituted;

(f) in sub-section (9), in the proviso,—

(i) in clause (a),—

(A) in sub-clause (i), for the words “ten per cent.”, the words “twelve per cent.” shall be substituted;

(B) in sub-clause (ii), for the words “fifteen per cent.”, the words “seventeen per cent.” shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the words “ten per cent”, the words “twelve per cent” shall be substituted.

3. Amendment of the First Schedule.—In the First Schedule to the principal Act,—

(a) in Part II, under the heading, “Surcharge on income tax”,—

(i) in item (a), for the words “ten per cent”, the words “twelve per cent” shall be substituted;

(ii) in item (b), for the words “eleven per cent.”, the words “thirteen per cent.”, shall be substituted;

(b) in Part III, in Paragraph-A under the heading “Surcharge on income-tax”,—

(i) in item (i).—

(A) in sub-item (A), for the words “ten per cent”, the words “twelve per cent”, shall be substituted:

(B) in sub-item (B), for the words “fifteen per cent.”, the words “seventeen per cent.”, shall be substituted.

(ii) in item (ii), for the words “ten per cent.”, the words “twelve per cent”, shall be substituted;

(c) in Part III, in Paragraph B, under the heading “Surcharge on income-tax”, for the words “ten per cent.”, the words “twelve per cent” shall be substituted;

(d) in Part III, in Paragraph C, under the heading “Surcharge on income-tax”, for the words “ten per cent.”, the words “twelve per cent.”, shall be substituted;

(e) in Part III, in Paragraph D, under the heading "Surcharge on income-tax", for the words "ten per cent.", the words "twelve per cent.", shall be substituted.

(f) in Part III, in Paragraph E, under the heading "Surcharge on income-tax", for the words "eleven per cent.", the words "thirteen per cent.", shall be substituted.

4. *Amendment of section 10 of the Income tax Act.*—In section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the Income-tax Act), in clause (23 C), after the eight proviso, the following proviso shall be inserted namely:—

"Provided also that any amount of donation received by the fund or institution in terms of clause (d) of sub-section (2) of section 80G which has been utilised for purposes other than providing relief to the victims of earthquake in Gujarat or which remains unutilised in terms of sub-section (5C) of section 80G and not transferred to the Prime Ministers' National Relief Fund on or before the 31st day of March, 2002 shall be deemed to be the income of the previous year and shall accordingly be charged to tax."

5. *Amendment of section 12.*—In section 12 of the Income-tax Act, after sub-section (2) and the explanation thereto, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(3) Notwithstanding anything contained in section 11, any amount of donation received by the trust or institution in terms of clause (d) of sub-section (2) of section 80G which has been utilised for purposes other than providing relief to the victims of earthquake in Gujarat or which remains unutilised in terms of sub-section (5G) of section 80G and not transferred to the Prime Ministers' National Relief Fund on or before the 31st day of March, 2002 shall be deemed to be income of the previous year and shall accordingly be charged to tax."

6. *Amendment of section 80G.*—In section 80G of the Income-tax Act.—

(a) in sub-section (1), in clause (i),—

(i) after the words, brackets, figures and letter "or in sub-clause (iiig)", the words, brackets, figures and letter "or in sub-clause (iiiga)" shall be inserted;

(ii) after the words, letter and brackets "or in clause (c)", the words, letter and brackets "or in clause (d)" shall be inserted;

(b) in sub-section (2),—

(i) in clause (a), after the sub-clause (iiig), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(iiiga) any fund setup by the State Government of Gujarat exclusively

for providing relief to the victims of earthquake in Gujarat";

(ii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

"(d) any sums paid by the assessee, during the period beginning on the 26th day of January, 2001 and ending on the 30th day of September, 2001, to any trust, institution or fund to which this section applies for providing relief to the victims of earthquake in Gujarat";

(c) after sub-section (5B), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(5C) This sub-section applies in relation to amounts referred to in clause (d) of sub-section (2) only if the trust or institution or fund is established in India for a charitable purpose and it fulfills the following conditions, namely:—

(i) it is approved in terms of clause (vi) of sub-section (5);

(ii) it maintains separate accounts of income and expenditure for providing relief to the victims of earthquake in Gujarat;

(iii) the donations made to the trust or institution or fund are applied for providing relief to the earthquake victims of Gujarat on or before the 31st day of March, 2002;

(iv) the amount of donation remaining unutilised on the 31st day of March, 2002 is transferred to the Prime Ministers' National Relief Fund on or before the 31st day of March, 2002;

(v) it renders accounts of income and expenditure to such authority and in such manner as may be prescribed, on or before the 30th day of June, 2002."

7. *Amendment of section 234C.*—In Section 234 C of the Income-tax Act, in sub-section (1), after the second proviso, the following shall be inserted, namely:—

"Provided also that nothing contained in this sub-section shall apply to any shortfall in the payment of the tax due on the returned income where such shortfall is on account of increase in the rate of surcharge under section 2 of the Finance Act, 2000 as amended by the Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2001 and the assessee has paid the amount of shortfall on or before the 15th day of March, 2001 in respect of the instalment of advance tax due on the 15th day of June, 2000, the 15th day of September, 2000 and 15th day of December, 2000."

8. *Instalment of advance tax in case of additional surcharge, payable on 15th March, 2001.*—Notwithstanding anything contained in the Income-tax Act, the surcharge payable under section 2 of, and Part III of the First Schedule to, the principal Act, as amended by this Ordinance,—

(i) in the case of an assessee, in respect of the instalment of "advance tax" paid or payable on or before the 15th day of June, 2000, the 15th day of September, 2000 and the 15th day of December, 2000, shall be payable on or before the 15th day of March, 2001;

(ii) in any case in which income-tax has to be charged under sub-section (4) of section 172 or sub-section (2) of section 174 or section 175 or sub-section (2) of section 176 of the Income-tax Act, shall be payable, only where income-tax is so charged after the date on which this Ordinance comes into force.

K. R. NARAYANAN,
President.

SUBHASH C. JAIN,
Secy. to the Govt. of India.

CORRIGENDUM

In the Indian Council of World Affairs Ordinance, 2001 (Ord. 1 of 2001) as published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section I, dated the 5th January, 2001 (Issue No. 4) at page 4, in line 9, for "caluse", read "clause".

LAW DEPARTMENT

(Legislation)

NOTIFICATION

[Shimla-2, the 28th April, 2001]

No. LLR-E(9)-2/2000-Leg. III.—The following Acts enacted by parliament and published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, Section-I are hereby republished in the Himachal Pradesh Rajpatra for the information of the general public:—

Sl. No.	Title	Date of the Gazette of India in which the Acts were published.
1.	The Taxation Laws (Amendment) Act, 2000 (Act No. 1 of 2001).	4-1-2001
2.	The Appropriation (No. 5) Act, 2000 (Act No. 2 of 2001).	4-1-2001
3.	The Appropriation (Railways) No. 5 Act, 2000 (Act No. 3 of 2001).	4-1-2001
4.	The Coal India (Regulation of Transfer and Validation) A.t, 2000 (Act No. 45 of 2000).	8-12-2000
5.	The Workmen's compansation (Amendment) Act, 2000 (Act No. 46 of 2000).	8-12-2000.
6.	The passport (Entry into India) Amendment Act, 2000 (Act No. 47 of 2000).	8-12-2000
7.	The Forefeiture (Repeal) Act, 2000 (Act No. 48 of 2000).	8-12-2000
8.	The Multimodal Transportation of Goods (Amendment) Act, 2000 (Act No. 44 of 2000).	5-12-2000
9.	The Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2000 (Act No. 49 of 2000).	11-12-2000
10.	The Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) Amendment Act, 2000 (Act No. 50 of 2000).	11-12-2000
11.	The Aircraft (Amendment) Act, 2000 (Act No. 51 of 2000).	11-12-2000
12.	The Immigration (Carriers, Liability) Act, 2000 (Act No. 52 of 2000).	11-12-2000

By order,
Sd/-
Secretary (Law).

Assented to on 4th January, 2001

THE TAXATION LAWS (AMENDMENT) ACT,
2000

(Act No. 1 of 2001)

AN

ACT

further to amend the Finance Act, 2000 and the Income tax Act, 1961.

Be it enacted by Parliament in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title.*—This Act may be called the Taxation Laws (Amendment) Act, 2000.

2. *Amendment of section 2.*—In section 2 of the Finance Act, 2000 (10 of 2000) (hereinafter referred to as the principal Act),—

(a) in sub-section (4), in clause (b), for the words “ten per cent”, the words “eleven per cent.” shall be substituted ;

(b) in sub-section (6), in Clause (b), for the words “ten per cent.”, the words “eleven per cent.” shall be substituted ;

(c) in sub-section (7), in clause (b), for the words, “ten per cent.”, the words “eleven per cent.” shall be substituted;

(d) in sub-section (8), in the third proviso, in clause (b), for the words “ten per cen .”, the words “eleven per cent” shall be substituted.

3. *Amendment of the first Schedule.*—In the First Schedule to the principal Act,—

(c) in Part II, under the heading “*Surcharge on income-tax*”, in clause (b), for the words “ten per cent.”, the words “eleven per cent.” shall be substituted;

(b) in Part III, in Paragraph E, under the heading “*Surcharge on income-tax*”, for the words “ten per cent.”, the words “eleven per cent.” shall be substituted.

4. *Amendment of section 234C.*—In section 234C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Income-tax Act), in sub-section (1), in clause (b), after the first proviso and before the *Explanation*, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that nothing contained in this sub-section shall apply to any shortfall in the payment of the tax due on the returned income where such shortfall is on account of increase in the rate of surcharge under section 2 of the Finance Act, 2000, (10 of 2000) as amended by the Taxation Laws (Amendment) Act, 2000, and the assessee has paid the amount of shortfall, on or before the 15th day of March, 2001 in respect of the instalment of advance tax due on the 15th day of June, 2000 the 15th day of September, 2000 and the 15th day of December, 2000.”.

5. *Payment of surcharge.*—Notwithstanding anything contained in the Income-tax Act, the surcharge payable under section 2 of, and Part-III of the First Schedule to, the principal Act, as amended by this Act,—

(i) in the case of an assessee being a domestic company shall, in respect of the instalment of “advance tax” paid or payable on or before the 15th day of June, 2000, the 15th day of September, 2000 and the 15th day of December, 2000, be payable on or before the 15th day of March, 2001;

(ii) in any case in which income-tax has to be charged under section 175 or sub-section (2) of section 176 of the said Act, shall be payable, in the case of an assessee being a domestic company, only where such income-tax is so charged after the date on which this Act receives the assent of the President.

Assented to on 4th January 2001

(ACT NO. 2 OF 2001)
THE APPROPRIATION (NO. 5) ACT, 2000
AN
ACT

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2000-2001.

Be it enacted by Parliament in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title.*—This Act may be called the Appropriation (No. 5) Act, 2000.

2. *Issue of Rs. 2639,09,00,000 out of the Consolidated Fund of India for the year 2000-2001.*—From and out of the Consolidated Fund of India there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule amounting in the aggregate of the sum of two thousand six hundred and thirty-nine crores and nine lakh rupees towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2000-2001 in respect of the services specified in column 2 of the Schedule.

3. *Appropriation.*—The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of India by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

No. of Vote	Services and purposes	Sums not exceeding		
		Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2	3		
		Rs.	Rs.	Rs.
1.	Department of Agriculture and Cooperation	Revenue 3,00,000 Capital 1,00,000	3,00,000 1,00,000
5.	Department of Chemicals and Petro- chemicals	Capital 98,67,00,000	..	98,67,00,000
8.	Department of Commerce	Revenue 13,81,00,000	..	13,81,00,000
12.	Department of Telecommunications	Revenue 1,00,000	..	1,00,000
13.	Department of Telecom Services	Capital 1,00,000	..	1,00,000
28.	Payment to Financial Institutions	Capital 100,00,00,000	..	100,00,00,000
30.	Transfers to State and Union territory Governments	Revenue 500,00,00,000 Capital —	— 500,00,00,000	500,00,00,000 500,00,00,000
33.	Department of Expenditure	Revenue 1,00,000	..	1,00,000
39.	Department of Public Distribution	Revenue 200,00,00,000	..	200,00,00,000
40.	Department of Consumer Affairs	Capital 3,00,00,000	..	3,00,00,000
41.	Department of Sugar and Edible Oils	Capital 45,00,00,000	..	45,00,00,000
47.	Police	Revenue 150,00,00,000 Capital 150,00,00,000	150,00,00,000 150,00,00,000
48.	Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	Revenue 1,00,000 Capital 13,32,00,000	1,00,000 13,32,00,000
50.	Department of Elementary Education and Literacy	Revenue 1,00,000	—	1,00,000
52.	Department of Women and Child Development	Revenue 1,00,000	..	1,00,000
54.	Department of Heavy Industry	Revenue 16,42,00,000 Capital 300,30,00,000	16,42,00,000 300,30,00,000
55.	Ministry of Information and Broadcasting	Revenue ..	1,26,00,000	1,26,00,000
56.	Ministry of Information Technology	Capital 8,42,00,000	..	8,42,00,000
58.	Law and Justice	Revenue 2,84,00,000	..	2,84,00,000
	CHARGED,— <i>Supreme Court of India</i>	Revenue ..	1,49,00,000	1,49,00,000
69.	Ministry of Power	Revenue 314,33,00,000 Capital 5,21,00,000	314,33,00,000 5,21,00,000
75.	Department of Bio-technology	Revenue 14,92,00,000	..	14,92,00,000
77.	Ministry of Statistics and Programme Implementation	Revenue 184,66,00,000	..	184,66,00,000
81.	Ministry of Textiles	Revenue 2,00,000	..	2,00,000
84.	Urban Development	Revenue .. Capital 1,00,000	26,00,000 ..	26,00,000 1,00,000
85.	Public Works	Capital 2,00,000	..	2,00,000
87.	Ministry of Urban Employment and Poverty Alleviation	Capital 1,00,000 Revenue 2,00,000	1,00,000 2,00,000
88.	Ministry of Water Resources	Capital 15,00,00,000	..	15,00,00,000
Total		1986,08,00,000	653,01,00,000	2639,09,00,000

Assented to on 4th January, 2001

THE APPROPRIATION (RAILWAYS) No. 5 ACT, 2000

ACT No. 3 OF 2001

AN
ACT

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2000-2001 for the purposes of Railways.

Be it enacted by Parliament in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title.*—This Act may be called the Appropriation (Railways) No. 5 Act, 2000.

2. *Issue of Rs. 30,000 out of the Consolidated Fund of India for the financial year 2000-2001.*—From and out of the Consolidated Fund of India there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of thirty thousand rupees towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2000-2001, in respect of the services relating to Railways specified in column 2 of the Schedule.

3. *Appropriation.*—The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of India by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE
(See section 2 and 3)

No. of Vote	Services and purposes	Sums not exceeding		
		Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2	3		
		Rs.	Rs.	Rs.
16.	Assets—Acquisition, Construction and Replacement—			
	Other Expenditure			
	Capital	4,000	..	4,000
	Railway Funds	26,000	..	26,000
	Total	30,000	..	30,000

Assented to on 8th December, 2000

THE COAL INDIA (REGULATION OF
TRANSFERS AND VALIDATION ACT, 2000

(ACT No. 45 OF 2000)

AN

ACT

to empower the Central Government to direct the transfer of land, or of the rights in or over land or of the right, title and interest in relation to a coal mine, coking coal mine or coke oven plant vested in the Coal India Limited or in a subsidiary company to any subsidiary company of Coal India Limited or any other subsidiary company and to validate certain transfers of such land or rights.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title.*—This Act may be called the Coal India (Regulation of Transfers and Validation) Act, 2000.

2. *Definitions.*—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “Coal India” means the Coal India Limited, a Government company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) having its registered office at Calcutta and includes its predecessor Government company, namely, the Coal Mines Authority Limited ;

(b) “subsidiary company” means the following subsidiary companies of Coal India, namely:—

(i) the Central Coal Field Limited, Ranchi and includes its predecessor Government

company, namely, the National Coal Development Corporation Limited, Ranchi;

(ii) the Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad ;

(iii) the Western Coal Fields Limited, Nagpur ;

(iv) the Eastern Coal Fields Limited, Sanctoria ;

(v) the Central Mine Planning and Design Institute Limited, Ranchi ;

(vi) the South Eastern Coal Fields Limited, Bilaspur ;

(vii) the Northern Coal Fields Limited, Singrauli ;

(viii) the Mahanadi Coal Fields Limited, Sambalpur.

and includes such other subsidiary company of Coal India as may be incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) from time to time ;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 (36 of 1972) or the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973, (26 of 1973) shall have the meanings, respectively, assigned to them in those Acts.

3. *Power of Central Government to direct transfer of land, rights, title or interest.*—(1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Central Government may, if it is satisfied that a subsidiary company is willing to comply, or has complied, with such terms and conditions as that Government may think fit to impose, direct, by notification in the Official Gazette, that the land or rights in or over such land or the right, title and interest in relation to a coal mine, coking coal mine or a coke oven plant vested

in the Coal India shall, instead of continuing to vest in the Coal India, vest in that subsidiary company or, where such land or right, title or interest vests in a subsidiary company, in another subsidiary company.

(2) Where the land or rights in or over such land or the right, title and interest in relation to a coal mine, coking coal mine or a coke oven plant vest in a subsidiary company under sub-section (1), such subsidiary company shall, on and from the date of such vesting, be deemed to have become the lessee in relation to such coal mine or coking coal mine as if a fresh mining lease in relation to such coal mine or coking coal mine had been granted to it under the Mineral Concession Rules, 1960 made under section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) for the maximum period for which such lease could have been granted under those rules, and all the rights and liabilities of Coal India or, as the case may be, the subsidiary company in relation to such coal mine or coking coal mine shall, on and from the date of such vesting, be deemed to have become the rights and liabilities, respectively, of subsidiary company first mentioned.

4. *Validation of certain transfers.*—A subsidiary company which was operating, or was in control of, any coal mine, coking coal mine, or coke oven plant which was vested in the Coal India or any other subsidiary company immediately before the commencement of this Act, shall be deemed to have been vested with the land or rights in or over such land or the right, title and interest in relation to such coal mine, coking coal mine or coke oven plant and such vesting shall be deemed to have been valid and effective at all material times as if a direction had been made by the Central Government under sub-section (1) of section 3 and accordingly no suit or other proceeding shall be instituted, maintained or continued in any court on the ground that such subsidiary company was not competent to operate or control such coal mine, coking coal mine or coke oven plant.

Assented to on 8th December, 2000

THE WORKMEN'S COMPENSATION (AMENDMENT) ACT, 2000

(ACT No. 46 OF 2000)

AN

ACT

further to amend the Women's Compensation Act, 1923.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title.*—This Act may be called the Workmen's Compensation (Amendment) Act, 2000.

2. *Amendment of section 2.*—In the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923) (hereinafter referred to as the principal Act), in section 2, in sub-section (1), in clause (n), the following brackets and words shall be omitted, namely:—

“(other than a person whose employment is of a casual nature and who is employed otherwise than for the purposes of the employer's trade or business)”.

3. *Amendment of section 4.*—In section 4 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) in clause (a), for the words “fifty thousand rupees”, the words “eighty thousand rupees” shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the words “sixty thousand rupees”, the words “ninety thousand rupees” shall be substituted;

(iii) in Explanation II, occurring after clause (b) and before clause (c), for the words “two thousand rupees” occurring at both the places, the words “four thousand rupees” shall respectively be substituted;

(b) in sub-section (4), for the words “one thousand rupees”, the words “two thousand and five hundred rupees” shall be substituted.

4. *Amendment of section 4A.*—In section 4A of the principal Act, for sub-section 3(A), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(3A) The interest and the penalty payable under sub-section (3) shall be paid to the workman or his dependant, as the case may be.”.

Assented to on 8th December, 2000

THE PASSPORT (ENTRY IN TO INDIA) AMENDMENT ACT, 2000

ACT No. 47 OF 2000

AN

ACT

further to amend the Passport (Entry into India) Act, 1920.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title.*—This Act may be called the Passport (Entry into India) Amendment Act, 2000.

2. *Amendment of section 3.*—In section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 (34 of 1920) (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (3), for the words “punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both”, the words “punishable with imprisonment for a term which may extend to five years, or with fine which may extend to fifty thousand rupees, or with both” shall be substituted.

3. *Insertion of new section 3A.*—After section 3 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

“3A. *Punishment for subsequent offences.*—Whoever having been convicted of an offence under any rule or order made under this Act is again convicted of an offence under this Act shall be punishable with double the penalty provided for the later offence.”.

4. *Amendment of section 4.*—In section 4 of the principal Act, in sub-section (2), for the words and figures “section 61 of the Code of Criminal Procedure, 1898”, (5 of 1898) the words and figures “section 57 of the Code of Criminal Procedure, 1973.” (2 of 1974) shall be substituted.

Assented to on 8th December, 2000

THE FORFEITURE (REPEAL) ACT, 2000

ACT No. 48 OF 2000

AN

ACT

to repeal the Forfeiture Act, 1859

BE it enacted by Parliament in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title.*—This Act may be called the Forfeiture (Repeal) Act, 2000.

2. *Repeal of Act 9 of 1859.*—The Forfeiture Act, 1859 is hereby repealed.

Assented to on 5th December, 2000

THE MULTIMODAL TRANSPORTATION OF GOODS (AMENDMENT) ACT, 2000.

(Act No. 44 of 2000)

AN

ACT

to amend the Multimodal Transportation of Goods Act, 1993.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows :—

1. *Short title.*—1. This Act may be called the Multimodal Transportation of Goods (Amendment) Act, 2000.

2. *Amendment of section 2.* In section 2 of the Multimodal Transportation of Goods Act, 1993 (28 of 1993) (hereinafter referred to as principal Act),—

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

(a) “carrier” means a person who performs or undertakes to perform for hire, the carriage or part thereof, of goods by road, rail, in land water-ways, sea or air ;;

(ii) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—

“(i) “goods” means any property including live animals, containers, pallets or such other articles of transport or packaging supplied by the consignor, irrespective of whether such property is to be or is carried on or under the deck;”;

(iii) in clause (j), for the words “road, rail”, the words “road, air, rail” shall be substituted ;

(iv) for clauses (k) and (l), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(k) “multimodal transportation” means carriage of goods, by at least two different modes of transport under a multimodal transport contract, from the place of acceptance of the goods in India to a place of delivery of the goods outside India ;;

(l) “multimodal transport contract” means a contract under which a multimodal transport operator undertakes to perform or procure the performance of multimodal transportation against payment of freight ;

(la) “multimodal transport document” means a negotiable or non-negotiable document evidencing a multimodal transport contract and which can be replaced by electronic data interchange messages permitted by applicable law ;

(v) in clause (m), in sub-clause (ii), for the words “not as an agent either of the consignor or of the carrier”, the words “not as an agent either of the consignor or consignee or of the carrier” shall be substituted ;

(vi) after clause (q), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(r) “special drawing rights” means such units of accounts as are determined by the International Monetary Fund ;

(s) “taking charge” means that the goods have been handed over to and accepted for carriage by the multimodal transport operator ;”.

3. *Amendment of section 4.*—In section 4 of the principal Act,—

(i) in sub-section (3), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) (i) that the applicant is a company, firm or proprietary concern, engaged either in the business of shipping, or freight forwarding in India or abroad with a minimum annual turnover of fifty lakh rupees during the immediately preceding financial year or an average annual turnover of fifty lakh rupees during the preceding three financial years as certified by a Chartered Accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) ;

(ii) that if the applicant is a company, firm or proprietary concern other than a company, firm or proprietary concern, specified in sub-clause (i), the subscribed share capital of such company or the aggregate balance in the capital account of partners of the firm, or the capital of the proprietor is not less than fifty lakh rupees.” ;

(ii) in sub-section (3), after the proviso, the following provisions shall be inserted, namely:—

“Provided further that any applicant who is not a resident of India and who is not engaged in the business of shipping shall not be granted registration unless he has established a place of business in India ;

Provided also that in respect of any applicant who is not a resident of India, the turnover may be certified by any authority competent to certify the accounts of a Company in that country.” ;

(iii) for sub-sections (4) and (5), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

“(4) A certificate granted under sub-section (3) shall be valid for a period of three years and may be renewed from time to time for a further period of three years at a time.

(5) An application for renewal shall be made in such form as may be prescribed and shall be accompanied by such amount of fees as may be notified by the Central Government ;

Provided that such fees shall not be less than rupees ten thousand and shall not exceed rupees twenty thousand.

(6) The competent authority shall renew the registration certificate granted under sub-section (3) if the applicant continues to fulfil the conditions as laid down at the time of registration.”.

4. *Amendment of section 6.*—In section 6 of the Principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

“(1) Any person aggrieved by, refusal of the competent authority to grant or renew registration under section 4 or by cancellation of registration under section 5, may prefer an appeal to the Central Government within such period as may be prescribed.”.

5. *Amendment of section 7.*—In section 7 of the principal Act, in sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the multimodal transport operator shall issue the multimodal transport document only after obtaining, and during the subsistence of a valid insurance cover.”.

6. *Amendment of section 9.*—In section 9 of the principal Act,—

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) the general nature of the goods, the leading marks necessary for identification of the goods, the character of the goods (including dangerous goods), the number of packages or units and the gross weight and quantity of the goods as declared by the consignor;”;

(ii) for clause (h), the following clause shall be substituted, namely:—

“(h) the date or the period of delivery of the goods by the multimodal transport operator as expressly agreed upon between the consignor and the multimodal transport operator;”;

(iii) for clause (k), the following clause shall be substituted, namely:—

“(k) freight payable by the consignor or the consignee, as the case may be, to be mentioned only, if expressly agreed by both the consignor and the consignee;”;

(iv) after clause (o), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the absence of any of the particulars listed above shall not affect the legal character of the multimodal transport document.”.

7. *Amendment of section 13.*—In section, 13 of the principal Act, in sub-section (1), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided further that the multimodal transport operator shall not be liable for loss or damage arising out of delay in delivery including any consequential loss or damage arising from such delay unless the consignor had made a declaration of interest in timely delivery which has been accepted by the multimodal transport operator.”.

8. *Amendment of section 14.*—In section 14 of the principal Act, in sub-section (1), for the *Explanation*, the following *Explanation* shall be substituted, namely:—

“*Expl. n.ation.*—For the purpose of this sub-section, where a container, pallet or similar article is stuffed with more than one package or units, the packages or units enumerated in the multimodal transport document, as packed in such container, pallet or similar article of transport shall be deemed as packages or units.”.

9. *Amendment of section 15.*—In section 15 of the principal Act, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the multimodal transport operator shall not be liable for any loss, damage or delay in delivery due to a cause for which the carrier is exempted from liability in accordance with the applicable law.”.

10. *Insertion of new section 20A.*—After section 20, the following section shall be inserted, namely:—

“20A. *Period of responsibility.*—The responsibility of the multimodal transport operator for the goods under this Act shall cover the period from the time he has taken the goods in his charge to the time of their delivery.”.

11. *Amendment of Act 26 of 1925.*—In the Indian Carriage of Goods by Sea Act, 1925, in Schedule, in Article I, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

“(c) “Goods” includes any property including live animals as well as containers, pallets or similar articles of transport or packaging supplied by the consignor, irrespective of whether such property is to be or is carried on or under deck;”.

Assented to on 11-12-2000

THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
(AMENDMENT) ACT, 2000
ACT No. 49 OF 2000

AN
ACT

further to amend the Protection of Human Rights Act, 1993.

Be it enacted by Parliament in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title.*—This Act may be called the Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2000.

2. *Amendment of Act 10 of 1994.*—After section 40 of the Protection of Human Rights Act, 1993, the following section shall be inserted, namely:—

“40A. *Power to make rules retrospectively.*—The power to make rules under clause (b) of sub-section (2) of section 40 shall include the power to make such rules or any of them retrospectively from a date not earlier than the date on which this Act received the assent of the President, but no such retrospective effect shall be given to any such rule so as to prejudicially affect the interests of any person to whom such rule may be applicable.”.

Assented to on 11-12-2000

THE PUNJAB MUNICIPAL CORPORATION LAW
(EXTENSION TO CHANDIGARH) AMENDMENT
ACT, 2000

ACT No. 50 OF 2000

AN
ACT

to amend the Punjab Municipal Corporation Law Extension to Chandigarh) Act, 1994.

Be it enacted by Parliament in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title.*—This Act may be called the Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) Amendment Act, 2000.

2. *Amendment of Act 45 of 1994.*—In the Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) Act, 1994, in Part-II of the Schedule, in section 4, in sub-section (3),—

(a) in clause (ii), for the words “municipal administration.”, the words “municipal administration : and” shall be substituted ;

(b) after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:—

“(iii) the member of the House of the People representing the constituency which comprises wholly or partly , the municipal area, with the right to vote.”.

Assented to on 11-12-2000

THE AIRCRAFT (AMENDMENT) ACT, 2000
(Act No. 51 of 2000)AN
ACT

further to amend the Aircraft Act, 1934.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title and commencement.*—(1) This Act may be called the Aircraft (Amendment) Act, 2000.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. *Amendment of section 11A of Act (22 of 1934).*—In section 11A of the Aircraft Act, 1934, for the words “with fine which may extend to one thousand rupees”, the words “with fine which may extend to ten lakh rupees” shall be substituted.

Assented to on 11-12-2002

THE IMMIGRATION (CARRIERS' LIABILITY) ACT, 2000

Act No. 52 OF 2000

AN
ACT

to make the carriers liable in respect of passengers brought by them into India in contravention of the provisions of the Passport (Entry into India) Act, 1920 and the rules made thereunder and matters connected therewith.—

BE it enacted by Parliament in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title and extent.*—(1) This Act may be called the Immigration (Carriers' Liability) Act, 2000.

(2) It extends to the whole of India.

2. *Definitions.*—(1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “carrier” means a person who is engaged in the business of transporting passengers by water or air and includes any association of persons, whether incorporated or not, by whom the aircraft or the ship is owned or chartered ;

(b) “competent authority” means the civil authority appointed under sub-paragraph (2) of paragraph 2 of the Foreigners Order, 1948 made under the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946) or any other officer notified by the Central Government in this behalf ;

(c) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act.

(2) Words and expressions not defined in this Act but defined in the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946) or the Passport (Entry into India) Act, 1920 (34 of 1920) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

3. *Liability of carriers for passengers brought into India.*—Where the competent authority is of the opinion that any carrier has brought a person in contravention of the provisions of the Passport (Entry into India) Act, 1920 (34 of 1920) and rules made thereunder into India, he may by order impose a penalty of rupees one lakh on such carrier :

Provided that no order shall be passed without giving the carrier an opportunity of being heard in the matter.

4. *Appeals.*—(1) An appeal shall lie against the order made under section 3 of this Act to the Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs authorised in this behalf by that Government.

(2) Every such appeal shall be preferred within

thirty days from the date of the order appealed against :

Provided that the appellate authority may, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal within the said period of thirty days, permit the appellant to prefer the appeal within a further period of thirty days.

(3) On receipt of any such appeal, the appellate authority shall, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard and after making such inquiry as it deems proper, make such order, as it may think fit, confirming, modifying or reversing the order appealed against.

(4) Every appeal shall be preferred on payment of such fees as may be prescribed.

5. *Recovery of penalty due to Government.*—Where any penalty imposed under this Act is not paid, the competent authority may recover the penalty so payable by seizing, detaining or selling—

(a) the aircraft or the ship ; or

(b) any goods on the ship or aircraft, belonging to the carrier.

6. *Bar of legal proceedings.*—No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Central Government or the competent authority or any officer of the Central Government or any other person exercising any powers or discharging any functions or performing any duty under this Act for anything in good faith done or intended to be done under this Act or any rule made thereunder.

7. *Application of Acts 16 of 1939, 34 of 1920 and 31 of 1946 not barred.*—The provisions of this Act and the rules made thereunder shall be in addition to, and not in derogation of, the Registration of Foreigners Act, 1939, the ‘Passport (Entry into India) Act, 1920 and the Foreigners Act, 1946 or the rules or orders made thereunder.

8. *Power to make rules.*—(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for—

(a) the fees which shall be paid for appeals under sub-section (4) of section 4 ;

(b) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

9. *Rules to be laid before Parliament.*—Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be ; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

10. *Power to remove difficulties.*—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order, do anything not inconsistent with such provisions for the purpose of removing the difficulty :

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament.

भाग 7—भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं

-शून्य-

अनुपारक

-शून्य-